दैनिक
भारत देश हमारा
मुख्य सम्पादक - जगजीत सिंह दर्दी
सम्पादकः अमृतपाल सिंह
DAILY BHARAT DESH HAMARA NEW DELHI

आरएनआई नं. 57282/1994 वर्ष 31 अंक 106 नई दिल्ली शनिवार 18 अप्रैल, 2026 मूल्य एक रुपया कुल पृष्ठ: 8 फोन 97111 01161 ईमेल : bharatdeshdelhi@gmail.com

सपा नेता गिरफ्तार

नोएडा 17 अप्रैल (निस) उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों द्वारा किए आंदोलन की समाप्ति के बाद अब इसने राजनीतिक रूप ले लिया है। मजदूरों की मांगों का मुद्दा बनाकर विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने से उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। आज एक सपा नेता को पकड़ लिया।

हादसे में 3 की मौत

कोटा 17 अप्रैल (निस) राजस्थान के कोटा जिले में बीतीर रात एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शहर के आरके पुरम थाना क्षेत्र के हैंगिंग ब्रिज के पास नया गांव के नजदीक हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गयी।

लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण संशोधन बिल
दो-तिहाई बहुमत जुटाने में सरकार नाकाम रही
विपक्ष ने एससी, ओबीसी को लेकर बिल का किया विरोध, विपक्ष को महंगा पड़ेगा-अमितशाह

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (निस) शुक्रवार को लोकसभा ने उस विधेयक को खारिज कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने और नई जनगणना कराए बिना परिसीमन करने का प्रावधान था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संविधान (131वां संशोधन) संशोधन विधेयक सदन में मतदान के दौरान 2/3 बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण पारित नहीं हो सका। मतदान के विभाजन में, 298 सदस्यों ने विधेयकों का समर्थन किया, जबकि 230 ने उनके खिलाफ मतदान किया। कुल वोटों की संख्या 528 थी। लोकसभा में किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सरकार ने इस विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद

अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके "रास्ते का रोड़ा" कौन है और उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अलग-अलग सीटों के बीच जनसंख्या के असंतुलन का हवाला देते हुए कहा कि यह परिसीमन से ही ठीक हो सकता है और विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए।लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक **शेष अंतिम पृष्ठ पर**

विपक्ष ने परिसीमन पर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
सरकार की नीयत खराब, परिसीमन पर चर्चा नहीं-राहुल

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस): संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर जारी बहस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तीकरण के नाम पर देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं का देश के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन मौजूदा विधेयकों का वास्तविक उद्देश्य महिला सशक्तीकरण नहीं है।उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 में पारित विधेयक ही वास्तविक महिला आरक्षण कानून था, जबकि वर्तमान प्रस्तावों के पीछे अलग राजनीतिक मंशा छिपी है।उन्होंने सरकार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया।

उनका कहना था कि भाजपा जातिगत जनगणना से बच रही है और ओबीसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने से कतरा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दलितों, पिछड़ों और उनकी महिलाओं के साथ समाज में ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण की भी सराहना की और उसे असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने वह कर दिखाया जो वह स्वयं वर्षों में नहीं कर पाए। उनका यह बयान हाल ही में लोकसभा में दिए गए प्रियंका गांधी के भाषण के संदर्भ में था, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों के साथ सरकार पर निशाना साधा था।संसद में जारी बहस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिया कि पूरा विपक्ष इन विधेयकों का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लाए गए संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया देश की राजनीतिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तेज होता जा रहा है, और आगामी वोटिंग को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म बना हुआ है।

भाजपा की गंदी राजनीति का जनता करारा जवाब देगी-केजरीवाल
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी, सीएम ने कहा-हम डरेंगे नहीं

लुधियाना 17 अप्रैल (निस) आप के रास सांसद अशोक मित्तल के घर छापेमारी के दो दिन बाद अब केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। शुक्रवार सुबह होते ही ईडी की टीमों ने मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित आवास और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

आने वाले घंटों में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे

जानकारी के मुताबिक, सुबह तड़के ही ईडी के अधिकारी लुधियाना पहुंचे और संजीव अरोड़ा की कोठी को चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर आवास के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जांच के दौरान किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। सूत्रों का कहना है कि यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन के सौदों में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में की जा रही है। बताया

जा रहा है कि ईडी की टीमें घर के अंदर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही हैं हालांकि, अभी तक विभाग की ओर से इस रेड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि या विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन चर्चा है कि आने वाले घंटों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद से ही शहर के सियासी माहौल में भारी गहमागहमी देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें जालंधर, कपूरथला और गुरुग्राम सहित कई ऐसे ठिकाने थे, जहां पर ई.डी. ने दबिश दी थी। आज की रेड पर **सीएम मान ने सख्त प्रतिक्रिया** देते हुए कहा कि हम इन छापों से डरने वाले नहीं। भाजपा ऐसी हरकतें करके हमारी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है लेकिन जनता उसे नाकाम कर देगी।

भाजपा की प्रतिक्रिया-पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई छापेमारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने बिना नाम लिए प्रतिक्रिया दी है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म **शेष अंतिम पृष्ठ पर**

राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए हरिवंश को फिर चुना, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हरिवंश पर सदन के गहरे विश्वास और संस्था में उनके बहुमूल्य अनुभव को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार चुना जाना सदन द्वारा उनके अनुभव, समावेशी दृष्टिकोण और गरिमामय कार्यशैली की स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर पड़ने वाले 17 अप्रैल के विशेष महत्व को रेखांकित किया। हरिवंश और चंद्रशेखर जी के घनिष्ठ संबंध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उपसभापति ने उनकी राजनीतिक यात्रा में उनके सहयोगी के रूप में कार्य किया और उनके जीवन पर पुस्तकें भी लिखीं।मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर जी की जयंती पर अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करना इस अवसर को विशेष रूप से सार्थक बनाता है। हरिवंश के पत्रकारिता के शानदार करियर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उच्च मानकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रभावशाली लेखन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान भी वे नियमित रूप से श्री हरिवंश के लेख पढ़ते थे।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, ट्रांजिट जमानत आगे बढ़ाने से किया इंकार

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (निस) सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक और झटका लगा है। यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बावजूद ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई है। इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सीमित दखल रखना चाहता है। छोटे-छोटे लेकिन सख्त सवालों के जरिए कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि

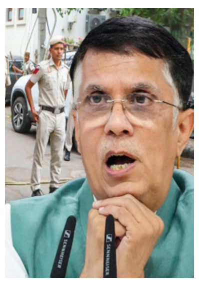

प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ऐसे में पवन खेड़ा के लिए यह सिर्फ कानूनी चुनौती नहीं, बल्कि समय और रणनीति की भी परीक्षा बन गई है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया गया कि अदालतें अब तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं को लेकर कितनी सख्त हो गई हैं। सिंघवी ने ट्रांजिट बेल बढ़ाने के लिए कई दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि अदालतें बंद हैं और असम जाने के लिए समय चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना। जस्टिस जे के माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि पवन खेड़ा तुरंत असम की सक्षम अदालत का रुख कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वहां सुनवाई पूरी तरह स्वतंत्र होगी और किसी भी पूर्व टिप्पणी का असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली।

किसान हितों के मामले में कृषि मंत्री चौहान की जीरो टोलरेंस की नीति

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) नई दिल्ली में मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनके सामने करेला की फसल में अमानक बीज और रोपे से हुए भारी नुकसान का मामला रखा, जिस पर शिवराज सिंह ने इसे किसानों की आजीविका पर सीधा प्रहार मानते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज के निर्देशों के बाद मामले में तेज़ कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी- नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी, जिस पर श्री चौहान ने तत्काल निर्देश जारी कर दिए।

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल के खिलाफ होगी सीबीआई जांच-हाईकोर्ट

लखनऊ 17 अप्रैल (निस) इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश आदेश दिया है। इसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था।यूपी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। इस पर जज ने मंजूरी दी। कहा कि एफआईआर करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल की थी। याची ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाये हैं।

राज्यसभा में राघव चड्डा का आप पर तंज, कहा-मैं हटाया गया उपनेता

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (निस)

राज्यसभा में शुक्रवार को एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने सदन में बोलते हुए अपनी ही पार्टी पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में हटाए गए उपनेता हैं और इसके बावजूद सदन में मौजूद हैं, जबकि उनकी पार्टी के अन्य प्रमुख नेता अनुपस्थित हैं। सांसद चड्ढा ने यह टिप्पणी उस समय की, जब राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने जाने पर अभिनंदन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और नवनियुक्त उपनेता सदन में मौजूद नहीं हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संजय सिंह और अशोक कुमार मित्तल पर निशाना साधा। इस दौरान चड्ढा ने उपसभापति को बधाई देते हुए उन्हें बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उनका यह बयान पार्टी के भीतर हालिया मतभेदों की ओर इशारा करता है।

संत कबीर जी की विचारधारा मौजूदा दौर में भी मानवता के लिए मार्गदर्शक-सीएम सैनी

चंडीगढ़, 17 अप्रैल (अमृतपाल सिंह): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि कबीर दास जी के विचार और शिक्षाएं आज के दौर में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि कबीर जी ने 15वीं शताब्दी में समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता, पाखंड और भेदभाव के विरुद्ध जो क्रांतिकारी आवाज उठाई थी, वह आज भी समाज को एकता, समरसता और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाती है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब के मोहाली में संत कबीर जी के जीवन एवं शिक्षाओं पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां संतों की वाणी गूंजती है, वह स्थान केवल सेमिनार नहीं बल्कि सत्संग का रूप ले लेता है। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अध्यात्म के माध्यम से शांति का अनुभव होता है।श्री सैनी ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब विश्व विभिन्न प्रकार के तनाव और संघर्षों से जूझ रहा है, ऐसे समय में

संत कबीर जी का दर्शन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके विचार मानव समाज के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उन्होंने संत कबीर जी को सच्चा मानवतावादी बताते हुए कहा कि उन्होंने जात-पात, ऊंच-नीच और हर प्रकार के भेदभाव का दृढ़ता से विरोध किया। उनकी वाणी की सरलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जो सीधे जन-मानस में उतर जाती थी और आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार संत-महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'संत-महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना' संचालित कर रही है। राज्य सरकार संत कबीर जी के समानता और समरसता के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। हाल ही में अंबाला से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया है और आगे भी अन्य तीर्थ स्थलों के लिए यात्राएं आयोजित की जा रही हैं।इसके अतिरिक्त, 'स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना' के तहत सिख धर्म से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही 'स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना' और 'कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना' के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को सहयोग दिया जा रहा है।

पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ....
बाढ़ की रोकथाम के लिए दरियाओं, चोओं एवं सेम नालों से गाद निकालने के लिए हरी झंडी

- आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह के लिए गाद निकालने वाली 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान

चंडीगढ़, 17 अप्रैल (निस)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रीमंडल ने जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों से गाद निकालने की इजाजत दे दी गई है। इस नीति के अंतर्गत दरियाओं, चोओं और नालों से निकाली गई सामग्री को मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले बाढ़ की तैयारियों में तेजी लाना और महत्वपूर्ण हिस्सों में दरियाओं के प्रवाह को बेहतर बनाना है।यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।""जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद

हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

बीजेपी विधायक के बेटे की थार से 5 लोग कुचले

शिवपुरी, 17 अप्रैल (निस) मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक गंभीर सड़क हादसे और कथित दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर अपनी थार कार से पांच लोगों को टक्कर मारने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। जानकारी के अनुसार, घटना करैरा थाना क्षेत्र की है। शिकायतकर्ता संजय परिहार ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ सुबह करीब 7:30 बजे बाइक से मजदूरी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार थार कार आई और बाइक सवार तीन मजदूरों तथा पैदल चल रही दो महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि कार दिनेश लोधी चला रहे थे और वाहन पर आगे और पीछे विधायक से जुड़े साइन भी लगे हुए थे, जिससे उसकी पहचान स्पष्ट हो रही थी। हादसे के बाद सामने आए वीडियो में सबूत मिल रहे हैं।

सम्पादकीय

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आशंका

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चिंता गहराती नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण भारत में भी ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल की कीमतों में लगभग 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी संभव है। यह संभावित वृद्धि ऐसे समय में सामने आई है जब देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल है और फिलहाल कीमतों को स्थिर रखा गया है। भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है, वहां कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व और रूस जैसे क्षेत्रों से आता है। ऐसे में वैश्विक राजनीतिक तनाव, युद्ध या आपूर्ति में कमी का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है। पिछले कुछ हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। करीब डेढ़ महीने के भीतर ही कीमतों में 27 डॉलर प्रति बैरल तक का उछाल दर्ज किया गया है। इस बढ़ोतरी ने तेल कंपनियों पर भारी दबाव बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए तक का नुकसान झेल रही हैं। कुल मिलाकर यह नुकसान प्रतिदिन लगभग 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पहले 2400 करोड़ रुपए के स्तर तक भी जा चुका था।

सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती किए जाने के बावजूद यह राहत पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार का तेल पर मिलने वाला राजस्व भी घटा है। जहां 2017 में यह 22 प्रतिशत था, वहीं अब घटकर करीब 8 प्रतिशत रह गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास भी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सीमित विकल्प बचे हैं। यदि सरकार पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी हटा भी दे, तब भी कंपनियों के घाटे की पूरी भरपाई संभव नहीं है। इस स्थिति का एक बड़ा कारण वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव भी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, विशेष रूप से ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ती खींचतान, कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर रही है। आपूर्ति में कमी और मांग में स्थिरता या वृद्धि के कारण कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। इसका असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईंधन की कीमतें बढ़ने का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिससे हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। खाद्य तेल, साबुन, शैंपू, बिस्किट और अन्य रोजमर्रा के उत्पाद महंगे होने लगते हैं। कई कंपनियां कीमतें बढ़ाने के बजाय पैकेट का आकार छोटा कर देती हैं, जिसे 'श्रिंकफ्लेशन' कहा जाता है। इससे उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से बोझ बढ़ता है।खाद्य तेल की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 57 प्रतिशत आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से इनके दाम भी 7 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। वहीं प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री महंगी होने से एफएमसीजी कंपनियों की लागत बढ़ गई है। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में भी लागत में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है। कंपनियां इसका बड़ा हिस्सा पहले ही ग्राहकों पर डाल चुकी हैं और आगे भी कीमतें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। कपड़ा उद्योग में सिंथेटिक फाइबर की कीमतें 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, जिससे कपड़ों के दाम भी बढ़ेंगे। पेंट उद्योग में भी लागत में वृद्धि के कारण 2 से 5 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरी स्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू देश का चालू खाता घाटा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही में यह 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट में पेट्रोल की औसत कीमतें 4 डॉलर प्रति गैलन के पार पहुंच गई हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है।

फिलहाल भारत में कीमतों को स्थिर रखा गया है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहना मुश्किल है। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया समाप्त होगी, कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और महंगाई में और वृद्धि होगी। इस परिस्थिति में सरकार के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। एक ओर कंपनियों के घाटे को कम करना जरूरी है, तो दूसरी ओर आम जनता को राहत देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना। अंततः यह स्पष्ट है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित वृद्धि केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी रखती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और तेल कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं और आम जनता को कितनी राहत मिल पाती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के उद्देश्य को लेकर अभी भ्रम की स्थिति

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक संतुलन स्थापित करना है। यह कदम केवल सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और लोकतंत्र की गुणवत्ता को मजबूत करने का एक व्यापक दृष्टिकोण भी है। किंतु इस ऐतिहासिक पहल के साथ कई गंभीर प्रश्न और आशंकाएँ भी उभरकर सामने आई हैंविशेषकर प्रॉक्सी नेतृत्व या बैक-डोर कंट्रोल का खतरा, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर वास्तविक सत्ता उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में होती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं िं? यह समस्या भारत तक सीमित नहीं है; विश्व के कई लोकतंत्रों में महिला आरक्षण या कोटा लागू होने के बाद इसी प्रकार की चुनौतियाँ सामने आई हैंइसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस अधिनियम के निहितार्थों, संभावित जोखिमों और सुधारात्मक उपायों का गहन विश्लेषण करें।ताकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव हमारे वि?न 2047 के लिए सटीक रूप से मील का पत्थर साबित हो। साथियों बात अगर हम मुद्दों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न यह हैकि क्या महिला जनप्रतिनिधियों का पारिवारिक पुरुषों द्वारा नियंत्रित होना मतदाताओं के विश्वास का हनन है?लोकतंत्र की मूल आत्मा प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। जब मतदाता किसी महिला को उसकी ईमानदार छवि, सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर चुनते हैं, तब वे अपेक्षा करते हैं कि वही महिला नीति-निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएगी। लेकिन यदि वास्तविक निर्णय उसके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, तो यह न केवल मतदाता के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी कमजोर करता है। भारत के कई राज्यों में पंचायत स्तर पर सरपंच

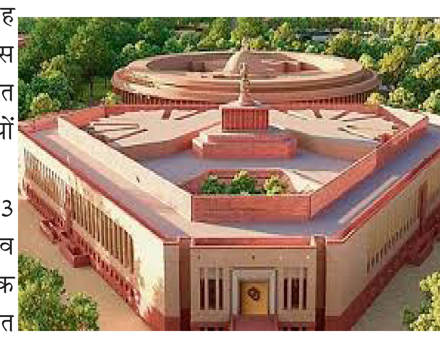

पति की प्रवृत्ति एक स्थापित वास्तविकता बन चुकी है, जहाँ निर्वाचित महिला केवल नाममात्र की मुखिया होती है और वास्तविक शक्ति पुरुषों के हाथों में रहती है। यह स्थिति महिलाओं के सशक्तिकरण के मूल उद्देश्य को ही निष्प्रभावी कर देती है और उन्हें मात्र एक तुच्छ राजनीतिक औजार बना देती है। साथियों दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद बैक-डोर नेतृत्व की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। जब किसी क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,तोराजनीतिक दल और प्रभावशाली पुरुष नेता अपने परिवार की महिलाओं को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले से ही स्थानीय निकायों में देखी जा चुकी है और यह संभावना है कि यह अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैल सकती है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देशों में महिला कोटा लागू होने के बाद प्रारंभिक वर्षों में प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा,जहाँ महिलाएँ केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि थीं। हालांकि समय के साथ, शिक्षा, राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के बढ़ने से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं है; उसके साथ संस्थागत और सामाजिक सुधार भी आवश्यक हैं। साथियों तीसरा बिंदु यह है कि क्या अयोग्य या अक्षम पुरुष नेता, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते, महिलाओं को आगे कर बैक-डोर से सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखेंगे? यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पहले से ही एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। ऐसे में, यदि किसी पुरुष नेता पर कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध है, तो वह अपनी पत्नी, बेटी या अन्य महिला रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता का उपयोग कर सकता है। यह न केवल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, बल्कि योग्य और स्वतंत्र महिला नेताओं के उभरने में भी बाधा डालता है। इस समस्या का समाधान केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में अति अति सतर्कता व पारदर्शिता से ही संभव है। साथियों चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला कैदियों की संख्या पिछले दो दशकों में 162 प्रतिशत बढ़ी है, जो पुरुष कैदियों की वृद्धि दर (77 प्रतिशत) से कहीं अधिक है। यह असंतुलन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या महिलाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, या उन्हें आपराधिक नेटवर्क द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? कई मामलों में यह पाया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे अपराधों में महिलाओं को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें कम संदेहास्पद माना जाता है। यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसे राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं। यदि आपराधिक तत्व महिलाओं को राजनीतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने लगें, तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ अवैध प्रवास और तस्करी की समस्या अधिक है, यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। साथियों पाँचवाँ मुद्दा आरक्षण के व्यावहारिक प्रभाव से जुड़ा है। यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है,और वहाँ पर्याप्त योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संभावना है कि अपेक्षाकृत कम सक्षम उम्मीदवार ही निर्वाचित हो जाएँ। यह स्थिति मतदाताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण हो सकती है,क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करने का अवसर नहीं मिलता। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सही है, लेकिन इसे व्यापक संदर्भ में देखना आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वंचित वर्ग को अवसर दिया जाता है, तो प्रारंभिक वर्षों में चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन समय के साथ वह वर्ग अपनी क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए, इस समस्या का समाधान

अमेरिकी नाकेबंदी, चीनी चुनौती एवं वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्णायक मोड़

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

होर्मुज़ नाकेबंदी स्थिति केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून,ऊर्जा सुरक्षा और महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है अमेरिका और चाइना के बीच होर्मुज़ में बढ़ता तनाव एक नए शीत युद्ध की आहट-मोदी ट्रंप बातचीत, भारत के लिए अवसर,वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करे

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में 15 अप्रैल 2026 को उत्पन्न घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर अस्थिरता के मोड़ पर ला खड़ा किया है। स्ट्रैट ऑफ़ होर्मूज़ पर अमेरिकी नाकेबंदी, चीनी टैंकरों की सक्रियता,ईरान-अमेरिका के बीच तनाव और इस्लामाबाद में असफल कूटनीतिक वार्ताओं ने मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है,जिसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है।यह स्थिति केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं,बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून,ऊर्जा सुरक्षा और महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की राजनीति अब केवल संवाद से नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन और रणनीतिक दबाव से संचालित हो रही है। एडवोकेट किस सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि इस बीच भारतीय पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति 14 अप्रैल 2026 को हुई 40 मिनट की बातचीत इस संकट के बीच भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।भारत,जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है,इस स्थिति से सीधे प्रभावित हो सकता है। इस वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने हमेशा संतुलन कारी नीति अपनाई है और इस संकट में भी वह कूटनीतिक समाधान की दिशा में प्रयास कर सकता है। यह भारत

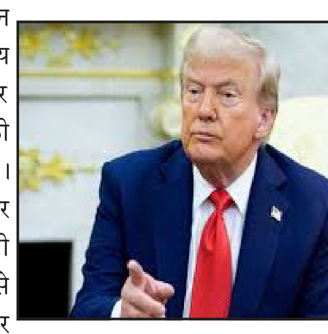

के लिए एक अवसर भी है कि वह वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करे। साथियों बात अगर हम होर्मुज़ का भू-राजनीतिक महत्व ऊर्जा की जीवनरेखा पर नियंत्रण को समझने की करें तो, स्ट्रैट ऑफ़ होर्मूज़ विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से प्रतिदिन लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल और गैस का परिवहन होता है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसके दोनों ओर ईरान और ओमान स्थित हैं। इस क्षेत्र पर नियंत्रण का अर्थ है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव, और यही कारण है कि अमेरिका, चीन और ईरान जैसे देश यहां अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखते हैं। होर्मुज़ पर किसी भी प्रकार की नाकेबंदी या सैन्य गतिविधि का सीधा असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है, जिससे यह क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन जाता है। साथियों बात अगर हमअमेरिकी नाकेबंदी- रणनीतिक दबाव या अंतरराष्ट्रीय विवाद इसको समझने की करें तो अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के माध्यम से ईरानी पोर्ट्स पर दबाव बनाने के लिए नाकेबंदी लागू की, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिक, कई युद्धपोत और दर्जनों एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। इस नाकेबंदी का उद्देश्य ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर करना था। हालांकि, इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में एकतरफा नाकेबंदी को वैध नहीं माना जाता। यूरोपीय देशों ने भी इस कदम का समर्थन नहीं किया, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई और यह स्पष्ट हुआ कि यह कदम केवल सामरिक नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम से भी भरा हुआ है। साथियों बात अगर हम ट्रंप की रणनीति- सफलता और विफलता का मिश्रण इसको समझने की करें तो, ट्रम्प द्वारा लागू की गई नाकेबंदी रणनीति को पूरी तरह सफल या विफल कहना कठिन है। एक ओर जहां कई जहाजों को वापस लौटना पड़ा और ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर कुछ टैंकर नाकेबंदी को पार करने में सफल भी रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह रणनीति आंशिक रूप से प्रभावी है,लेकिन इसमें कई कमजोरियां भी हैं।इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी और कानूनी विवादों ने इस योजना की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। इस स्थिति में ट्रंप प्रशासन को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वह अधिक प्रभावी और वैध तरीके से अपने उद्देश्यों को सटीक रूप से प्राप्त कर सके। साथियों बात अगर हम चीनी टैंकर की चुनौती- वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत इसको समझने की करें तो 15 अप्रैल 2026 को चीनी टैंकर रिच स्टैरी अमेरिकी नाकेबंदी को पार करने में असफल रहा,जबकि एक दिन पहले वह सफलता पूर्वक गुजर गया था। यह घटना न केवल अमेरिकी रणनीति की सीमाओं को दर्शाती है, बल्कि चाइना की बढ़ती वैश्विक भूमिका का भी संकेत देती है। यह टैंकर यूनाइटेड अरब अमीरात के हमरियाह पोर्ट से चला था और इसमें भारी मात्रा में मेथेनॉल लोड था। चीन का यह कदम स्पष्ट करता है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों और दबावों को चुनौती देने के लिए तैयार है और अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार है। यह घटना एक बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष की ओर संकेत करती है।

बिहार में भाजपा का युग: एक नया राजनीतिक अध्याय

-सौरभ वार्ष्णेय

राजनीति भी ऐसा मौसम है पता नहीं कब क्या कुछ हो जाये ? ऐसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ नहीं कहा जा सकता कब उनका फैसला बदल जाये। वैसे भी बिहार की राजनीति लंबे समय तक जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की जटिलताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का उभार राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक सोच, विकास के एजेंडे और नेतृत्व शैली में भी परिवर्तन का द्योतक है। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना और बिहार के वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कोई अचानक हुई घटना नहीं है। यह एक लंबी रणनीतिक यात्रा का परिणाम है, जिसमें संगठन की मजबूती, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और केंद्र की नीतियों का प्रभाव शामिल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं—जैसे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना—ने राज्य के ग्रामीण और गरीब वर्गों में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ाई है। इससे पार्टी को एक मजबूत जनाधार बनाने में मदद मिली है। हालांकि, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता और राष्ट्रीय जनता दल जैसे प्रभावशाली दल अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में भाजपा का यह उभार एक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक वातावरण तैयार करता है, जहां सत्ता की लड़ाई और अधिक दिलचस्प और जटिल हो गई है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने विकास के वादों को जमीन पर उतारे। बिहार आज भी बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। भाजपा को इन क्षेत्रों में ठोस सुधार करना होगा। यह उसके लिए एक स्थायी राजनीतिक आधार बनाने का अवसर हो सकता है। इसके अलावा, सामाजिक समरसता और जातीय संतुलन बनाए रखना भी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी होगी। बिहार की सामाजिक संरचना बेहद संवेदनशील है, जहां छोटी-सी राजनीतिक चूक भी बड़े सामाजिक तनाव का कारण बन

सकती है। बिहार में भाजपा का उभरता हुआ युग एक परिवर्तनशील दौर का प्रतीक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव राज्य को विकास और स्थिरता की ओर ले जाता है या फिर यह केवल सत्ता के नए समीकरणों तक ही सीमित रह जाता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की राजनीतिक धारा को भी प्रभावित करेगा।

बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना

ऐसे में भाजपा ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है तो यह तय है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक संदेश और रणनीतिक बदलाव का संकेत होगा। सबसे पहले, यह कदम भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास के रूप में देखा जाएगा, जिसमें वह बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान को और मजबूत करना चाहती है। लंबे समय तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की राजनीति करने के बाद, भाजपा अब अपने चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतार दिया है। सम्राट चौधरी का सामाजिक आधार भी इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाता है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना सामाजिक प्रतिनिधित्व के नए समीकरण साध सकता है और भाजपा को उन वर्गों में और गहराई तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, जहां अब तक अन्य दलों का प्रभाव रहा है। हालांकि, यह रास्ता आसान नहीं होगा। बिहार जैसे राज्य में प्रशासनिक अनुभव, गठबंधन संतुलन और जमीनी पकड़ बेहद महत्वपूर्ण होती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं की मजबूत राजनीतिक पकड़ के बीच सम्राट चौधरी को अपनी स्वीकार्यता साबित करनी होगी। इसके अलावा, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस बदलाव के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं को आकर्षित कर पाती है या नहीं। क्योंकि आज की राजनीति में केवल जातीय समीकरण ही नहीं, बल्कि विकास, रोजगार और सुशासन भी उतने ही अहम मुद्दे बन चुके हैं। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विश्वास और प्रदर्शन की एक बड़ी परीक्षा होगी। अगर हम सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करे तो बिहार की समकालीन राजनीति में तेजी से उभरते नेतृत्व का उदाहरण माना जाता है। उनका सफर छात्र राजनीति से लेकर राज्य की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रहा है। सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और धीरे-धीरे मुख्यधारा की राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। सम्राट चौधरी ने अपने करियर में कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बीजेपी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी के रणनीतिक निर्णयों के चलते सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में प्रमुख चेहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री बने तो यह उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक कौशल और सामाजिक समीकरणों को साधने की क्षमता का परिणाम माना जाएगा। उनकी राजनीतिक विशेषताएं। ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आक्रामक और स्पष्ट वक्ता सहित संगठन और जनाधार दोनों पर पकड़ रखते हैं। सम्राट चौधरी का करियर यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में लगातार सक्रियता, रणनीति और समय के अनुसार निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। वे आज राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। 2026 के अनुसार भाजपा के 16 वें राज्य के मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी ।

29 अप्रैल को होगा महापौर और उपमहापौर चुनाव जारी होगी अधिसूचना

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) एमसीडी में महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव 29 अप्रैल को कराए जाएंगे। इस संबंध में महापौर राजा इकबाल सिंह ने चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चुनाव के लिए सदन की बैठक भी 29 अप्रैल को बुलाई गई है जबकि अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। उम्मीदवार चाहें तो तय समय सीमा के भीतर अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। निगम सचिव कार्यालय में पार्षद अपने-अपने दलों की ओर से नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि, एमसीडी में अब एक भी निर्दलीय पार्षद नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सदन में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। एमसीडी में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण इन दोनों प्रमुख पदों पर उसकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है।

दिल्ली में जनगणना का पहला चरण घर-घर होगा सर्वे डिजिटल तरीके से जुटेगा डेटा

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली में जनगणना का पहला चरण गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह का काम शुरू होगा। यह प्रक्रिया आने वाले दशक में शासन और नीतिगत निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण करने की तैयारी कर चुके हैं। पहले चरण को हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा जाता है, जिसमें घरों, इमारतों और जीवन स्थितियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। यह चरण व्यक्तियों की गणना के बजाय शहर की हर संरचना और आवास का मानचित्रण करने पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान निवासियों से 33 प्रश्नों के एक सेट के जरिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, घर के स्वामित्व की स्थिति और घर के मुखिया का नाम व लिंग जैसी जानकारी ली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह पूरा अभियान डिजिटल माध्यम से संचालित होगा। गणनाकर्ता अपने उपकरणों में एक विशेष मोबाइल एप के जरिए डेटा दर्ज करेंगे, जिससे सटीकता और दक्षता बढ़ेगी। पहला चरण दो अलग-अलग 30 दिवसीय चक्रों में चलेगा। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी क्षेत्रों में यह 16 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा, जबकि दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में 16 मई से 15 जून तक यह लागू होगा। जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अलग-अलग ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। दूसरा चरण, जिसमें व्यक्तियों की गणना होगी, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर तय समय के अनुसार किया जाएगा।

दिल्ली में फायर सर्विस की समीक्षा एलजी ने सुधार पर दिया जोर

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू ने हाल ही में दिल्ली फायर सर्विस के कामकाज की समीक्षा की। इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाना है। इस समीक्षा में आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और कर्मियों की क्षमता को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एलजी ने दिल्ली फायर सर्विस नियम, 2010 में प्रस्तावित संशोधनों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने निवासियों, व्यापारियों और कारोबारी वर्ग के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करेगा कि नियामक ढांचा समावेशी, व्यावहारिक और प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप, हर नियामक ढांचा 'ईज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इससे मजबूत फायर सेफ्टी सुनिश्चित होगी। साथ ही, नागरिकों पर अनावश्यक बोझ भी नहीं पड़ेगा। बढ़ते गर्मी के तापमान को देखते हुए विभाग की समर एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई। एलजी ने इस दौरान सतर्कता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। नागरिकों को निवारक उपायों, नियामक सुरक्षा और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया गया। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया।

धमकी भरे ईमेल के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को मिली सिक्योरिटी

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को लगातार मिल रही बम धमकियों और हालिया सुरक्षा चूक के बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा परिसर की सुरक्षा भी पूरी तरह मजबूत की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाते हुए, उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा कवर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है, जब विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष कार्यालय को आधिकारिक ईमेल आईडी पर करीब 6 से 7 धमकी भरे ईमेल मिले। इन ईमेल में बम धमाके की धमकी दी गई थी। इन धमकियों के अलावा हाल ही में विधानसभा परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक भी सामने आई थी। एक व्यक्ति विधानसभा के गेट पार कर अंदर पहुंच गया और अध्यक्ष की गाड़ी में एक संदिग्ध वस्तु रखकर चला गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पूरे इंतजाम की समीक्षा की गई। नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब विजेंद्र गुप्ता के साथ 24 घंटे विशेष सुरक्षा टीम तैनात रहेगी। उनके काफिले के साथ हर समय एक एस्कॉर्ट वाहन चलेगा। सुरक्षा टीम की कमान एक प्रभारी अधिकारी के हाथ में होगी, जबकि प्रशिक्षित कमांडो भी साथ रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों और आधिकारिक दौरों के दौरान भी उनकी सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी रहेगी।

अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव में एसएफआई फिर जीती

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव 2026 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एसएफआई इस चुनाव में सबसे बड़ी छात्र संगठन बनकर उभरी है और अलग-अलग कैंपस में कुल 21 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त हासिल की है। कश्मीरी गेट कैंपस में एसएफआई को 25 सदस्यीय परिषद में 13 काउंसलर का समर्थन मिला, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। वहीं, करमपुरा कैंपस में एसएफआई ने 7 में से 5 सीटें जीतकर दमदार प्रदर्शन किया, जबकि कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। लोदी रोड कैंपस में भी एसएफआई ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर तीनों कैंपस में एसएफआई ने मजबूती से अपनी स्थिति कायम रखी और अन्य छात्र संगठनों से काफी आगे रही।

युवती को अगवा कर मारपीट करने वाले कथित प्रेमी और परिवार की तलाश जारी

भोपाल 17 अप्रैल (निस) मिसरोद इलाके में एक युवती का उसके पूर्व प्रेमी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसे एक होटल से अगवा कर उसकी जमकर पिटाई लगाई। इतना ही नहीं आरोपियो ने युवती के दोस्त के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी और मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 26 वर्षीय युवती अवधपुरी इलाके में रहती है। करीब 10 साल से उसकी शुभम नाम के युवक से नजदीकियां थी। उनकी शादी की बात भी चल रही थी। इसी दौरान युवती की नौकरी निजी कंपनी में लग गई। बाद में युवती की दोस्ती राहुल नाम के युवक से हो गई। युवती ने जब शुभम से बात करना कम कर दिया तो तब उसे संदेह हुआ की युवती की नजदीकियां अपने सहकर्मी राहुल से बढ़ गई है, जिस कारण वह उससे दुरियां बना रह है। इसके बाद शुभम ने दोनों को सबक सिखाने की योजना बनाई। मंगलवार सुबह शुभम युवती को स्कूटर से केंद्रीय विद्यालय के पीछे स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने राहुल को भी बुला लिया। इसी दौरान शुभम ने अपने ममेरे भाइयों और भाभी के साथ मिलकर दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाद में उन्हें जबरन कार में बैठाकर बरखेड़ा पठानी ले जाया गया, जहां फिर से मारपीट की गई और बाद में छोड़ दिया। हालांकि होटल में हंगामा देख कर्मचारियों ने डायल 112 पर सूचना दी थी। पुलिस को वाहन का नंबर मिला, जिसके आधार पर युवती से सपंर्क किया गया। महिला अधिकारी ने उससे पूछताछ की लेकिन उसने कहा कि शुभम कुमार उसका पुराना दोस्त है, और वह किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहती है। मारपीट में चोट लगने के कारण युवती को एम्स में भर्ती कराना पड़ा। बाद में युवती अपने बयान से बदल गई और शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने युवती की शिकायत पर शुभम कुमार, अमित कश्यप, शैलेष कश्यप और नेहा कश्यप पर अपहरण का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिये है।

धमतरी नगर निगम में स्टाफ संकट: 356 में से 172 पद खाली, कामकाज प्रभावित

जिले का नगर निगम इन दिनों अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात यह हैं कि अधिकांश काम प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहा है, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों प्रभावित हो रही हैं। साल 2012 में नगर निगम गठन और राज्य सरकार से सेटअप की मंजूरी मिलने के बावजूद अब तक आवश्यक पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है। वर्तमान में पुराने नगर पालिका परिषद के स्टाफ के सहारे ही निगम का कामकाज चलाया जा रहा है। निगम के स्वीकृत सेटअप में कुल 356 पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 184 पद ही भरे गए हैं, जबकि 172 पद अब भी रिक्त पड़े हैं। इस कारण प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।

जलभराव पर तंज: नाव खरीद लो सामान्य सभा में पार्षद का अफसरों पर वार, सदन में हंगामा

बिलासपुर 17 अप्रैल (निस) नगर निगम की सामान्य सभा में सोमवार को पानी निकासी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भाजपा पार्षद जय वाधवानी ने शहर में जलभराव की समस्या को लेकर निगम अफसरों पर तीखा तंज कसते हुए कहा-हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को नाव खरीदने की सलाह देनी पड़ेगी। इस बयान के बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और पार्षदों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। हर बारिश में डूबता शहर, बढ़ती नाराजगी, पार्षदों ने आरोप लगाया कि— हल्की बारिश में भी सड़कों पर पानी भर जाता है, नालियों की सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, जय वाधवानी ने कहा कि जब हालात इतने खराब हैं तो जनता को नाव खरीदने की सलाह देना ही बचता है, क्योंकि निगम की व्यवस्था भरोसे के लायक नहीं रह गई है। सामान्य सभा में फाइलों में लंबित कार्यों का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। पार्षदों ने बताया कि— करीब 500 से अधिक प्रस्ताव अब भी अटके हुए हैं, स्वीकृति के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहे, अधिकारी जवाब देने से बचते हैं, इस पर पार्षदों ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। सदन में तीखी नोकझोंक, बयान पर बवाल नाव खरीद लो वाले बयान के बाद— कुछ पार्षदों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया वहीं कई पार्षदों ने कहा कि यह जमीनी हकीकत को दर्शाता है सदन में कुछ देर के लिए शोर-शराबा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही प्रभावित हुई। अफसरों दिया जवाब काम जारी, जल्द सुधार, निगम अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा जलनिकासी के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं, बजट और तकनीकी कारणों से देरी हुई, आने वाले समय में व्यवस्था सुधारी जाएगी। लेकिन पार्षद इन जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आए और ठोस कार्रवाई की मांग की।

तीन महीने तक घर में होती रही 'सोने की अदला-बदली',

सकरी क्षेत्र के आसमा सिटी निवासी व्यवसायी सतीश मिश्रा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उनके ही घर में अक्टूबर से दिसंबर तक करीब तीन महीने तक चोरी की ऐसी वारदात होती रही, जिसमें असली सोने को बड़ी चालाकी से नकली सोने से बदल दिया गया — और हैरानी की बात ये है कि इस दौरान पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सतीश मिश्रा के मुताबिक, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत 19 फरवरी 2026 और 26 मार्च 2026 को थाने में लिखित रूप से की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही नजर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ परिचित लोगों की भूमिका संदिग्ध है, बावजूद इसके पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ने के बजाय ठंडी फाइलों में दबी हुई है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। मिश्रा ने यह भी बताया कि 5 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच उनके बैंक खाते से सकरी स्थित एटीएम से कई बार पैसे निकाले गए।

दिन दहाड़े सड़क पर किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या

भोपाल 17 अप्रैल (निस) शहर के देहात इलाके के बैरसिया क्षेत्र में किराना कारोबारी मोहम्मद हनीफ की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। मृतक के भाई अनीस का कहना है कि मृतक हनीफ ने एक दर्जन से अधिक लोगों को उधार माल दिया था, जिसका उन्हें करीब 50 लाख रुपए लेना था। अनीस ने हिसाब की डायरी को पुलिस को सौंपी है। सूत्रो के मुताबिक अब पुलिस उन सभी लोगों को थाने तलब कर पूछताछ करने की तैयारी में है, जिनसे मृतक हनीफ को लाखों रुपए लेना थे। वहीं पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर उन्हें आखिरी समय में फोन करने वालों से भी पूछताछ करेगी।

- बाइक सवार हमलावर ने बीच सड़क पर मारी थी दो गोलियां-पुलिस ने बताया कि हनीफ (42) पिता मोहम्मद शफीक, वार्ड नंबर 7 बैरसिया में रहते है। वह स्थानीय स्तर पर किराना व्यवसाय से जुड़े थे। रोजमर्रा के काम के सिलसिले में आसपास के क्षेत्रों में उनका आना-जाना रहता था। बुधवार को वह घर में खेजड़ा मेसर स्थित अपनी खेती की जमीन पर जाने का कहकर निकले थे। बाद में हनीफ का शव उनके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ढाबे के पास मिला। जांच के दौरान मृतक के सीने में गोली लगने के निशान पाए गए, जिससे साफ हुआ की उनकी हत्या की गई है। घटनास्थल से उनकी बाइक भी बरामद की गई है। परिवार वालो का कहना है की दोपहर एक बजे किसी ने कॉल कर उन्हें बुलाया था। वह घर से कुछ देर में आने का बोलकर निकले थे। बुधवार शाम सा? चार बजे उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि परिजनों ने हत्या के लिए किसी संदेही का नाम पुलिस को नहीं बताया है। पुलिस अफसरो का कहना है की मृतक के सीने में दो गोली लगने के निशान हैं। हत्याकांड को क्यों और किसने अंजाम दिया फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की अब तक की जांच में यह साफ हो गया है, कि हमलावर बाइक सवार था। उसने सरेराह हनीफ को रोका। बहस की और सीने और कंधे में दो गोलियां मारकर फरार हो गया। गर्मी के कारण स?क सुनसान थी। आस पास कोई खास आबादी भी नहीं थी, लिहाजा आरोपी वारदात को आसानी से अंजाम देकर भाग निकला। पुलिस मामले की सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सुराग जुटाने के लिये पास में स्थित ढाबे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है।

एनकाउंटर में ढेर महिला नक्सली रूपी का तेलंगाना में अंतिम संस्कार, लाल झंडों और 'हिड़मा गीत' पर नाच का वीडियो वायरल

कांकेर 17 अप्रैल (निस) जिले में 13 अप्रैल को मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली लीडर रूपी रेड्डी का अंतिम संस्कार तेलंगाना के मेडक जिले में किया गया। अंतिम संस्कार से पहले निकाली गई शव यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग लाल झंडे लेकर डीजे पर नाचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पोस्टमॉर्टम के बाद रूपी का शव परिजनों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद उसे तेलंगाना ले जाया गया। 14 अप्रैल को मेडक जिले में अंतिम संस्कार से पहले शव यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान डीजे पर 'मेरे जंगल का सीना, चीर डाला तूने' जैसे गीत बजाए गए और कुछ लोग नाचते हुए दिखाई दिए। वायरल वीडियो में कुछ पोस्टर भी नजर आए, जिनमें सरकार से रोजगार और सम्मान देने की मांग लिखी गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। कांकेर पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना तेलंगाना की है, इसलिए इस पर स्थानीय स्तर पर ही कार्रवाई होगी। एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि एनकाउंटर के अगले दिन ही रूपी रेड्डी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के माचपल्ली, आरामझरिन और हिड़ूर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसी मुठभेड़ में एरिया कमेटी मेंबर (एसीएम) रूपी रेड्डी मारी गई थी। मौके से एक पिस्टल भी बरामद की गई थी। पुलिस के मुताबिक, रूपी रेड्डी लंबे समय से सक्रिय नक्सली थी और उसे कई बार आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, लेकिन वह लगातार संगठन से जुड़ी रही। बस्तर क्षेत्र में बड़े नक्सली कैडर के कमजोर पड़ने के बाद वह प्रमुख सक्रिय चेहरों में शामिल थी।

सोशल मीडिया पर दोस्ती, शादी का झांसा: दुर्ग के युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज

सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। भानुप्रतापुर की रहने वाली युवती की शिकायत पर मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान साल 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए दुर्ग के सिकोला भाटा निवासी सौरभ राजपूत से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया। इसके बाद 5 मार्च 2026 को वह उससे मिलने दुर्ग पहुंची। शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे अपने बड़े भाई के घर ले गया, जहां शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं माना। घटना के बाद युवती कुछ दिनों तक पाटन में अपनी बुआ के घर रही। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे उज्जैन भी लेकर गया, जहां भी उसने लगातार संबंध बनाए। दुर्ग लौटने के बाद आरोपी ने उसे अपने पास रखा और शादी का वादा कर बार-बार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने बताया कि 11 अप्रैल 2026 को आरोपी उसे ग्राम संबलपुर अपने नानी के घर ले गया, जहां एक रात रुकने के दौरान फिर दुष्कर्म किया।

बिस्तर से सीबीएसई बोर्ड टॉपर तक: कैंसर से जंग लड़ रहे आरव वत्स ने 96.6 प्रतिशत लाकर पेश की मिसाल

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) आरव वत्स ने कैंसर से जूझते हुए सीबीएसई 10वीं में 96.6 प्रतिशत अंक हासिल कर मिसाल कायम की है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, साकेत के छात्र आरव को 2022 में लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा का पता चला था। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, साकेत के छात्र आरव वत्स पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की सेकेंडरी कक्षा में 96.6 प्रतिशत अंक लाने वाले आरव की कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और अटूट विश्वास की मिसाल है। वर्ष 2022 में जब उन्हें कैंसर (लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा) जैसी गंभीर बीमारी का पता चला, तो पूरा परिवार टूट गया। लेकिन इस कठिन समय में आरव और उनके परिवार ने खुद को संभाला और सकारात्मक सोच के साथ इस लड़ाई को स्वीकार किया। पिता डॉ. अजय वत्स बताते हैं कि बीमारी का पता चलते ही आरव का लंबा इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नियमित एमआरआई स्कैन और सर्जरी जैसे कठिन दौर से गुजरते हुए उन्होंने कई बार शारीरिक कमजोरी का सामना किया। 2022 में स्पाइन की सर्जरी के बाद समय ऐसा भी आया जब वह पूरे एक साल तक बिस्तर पर रहे। इस दौरान बस बेटे को यही समझाया कि परिस्थिति जो भी हो पाजिटिव रहना है और हम तुम्हारे साथ हैं।

लालू यादव और तेजस्वी यादव को राहत

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला टाल दिया है। दिल्ली की अदालत अब इस मामले में आरोप तय करने का निर्णय 6 मई को सुना सकती है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर में फैसला टाल दिया। कोर्ट मामले में आरोप तय करने पर छह मई को फैसला सुना सकती है।

पुलिस को 14 दिन के अंदर करनी होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सख्ती

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) अब किसी भी आपराधिक शिकायत की प्रारंभिक जांच को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद देशभर में पुलिस विभाग को स्पष्ट कर दिया गया है कि शिकायत मिलने के बाद अधिकतम 14 दिनों के भीतर जांच पूरी कर आगे की कार्रवाई तय करनी होगी। यदि तय समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा है कि जांच में देरी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है और पीड़ितों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जांच की प्रगति का रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से रखने को कहा गया है, ताकि जवाबदेही तय की जा सके। इस फैसले के बाद पुलिस तंत्र में सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।

डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली साइबर पुलिस ने आनंद कुमार नामक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं से लगभग 2 करोड़ रुपये ठग चुका है। दक्षिणी पश्चिमी जिले की साइबर थाने की टीम ने शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपित 24 परगना, बंगाल का रहने आनंद कुमार डेटिंग और मैट्रिमोनियल एप पर डॉक्टर, प्रोड्यूसर, वकील, बिजनेसमैन आदि की नकली प्रोफाइल बनाकर 500 से अधिक महिलाओं को धोखा दे चुका है। निजी कंटेंट को वायरल करने की धमकी देकर महिलाओं से लगभग दो करोड़ रुपये की ठगी की। आरोपी के पास से बरामदगी चार स्मार्टफोन, आठ सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड, चार सोने के ब्रेसलेट, पांच सोने की चेन बरामद किए गए। इस तरह के अपराधों में उसकी पहले भी दो बार संलिप्तता मिली है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) जज को सुनवाई से अलग करने की मांग वाली अर्जी पर दाखिल अतिरिक्त शपथपत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष पेश हो सकते हैं। केजरीवाल यह बता सकते हैं कि बुधवार को दायर किया गया उनका हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है। हलफनामे में केजरीवाल ने कहा था कि चूंकि न्यायमूर्ति शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं, इसलिए उनके पक्ष में हितों का टकराव है।

चीनी टेलीग्राम से जुड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ बैंक मैनेजर समेत तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) पूर्वी दिल्ली पुलिस ने चीनी टेलीग्राम चैनल से जुड़े एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर और चाचा-भतीजे सहित तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह गिरोह भारतीयों के बैंक खाते खाली करने के लिए एपीके फाइल भेजता था और पकड़े गए आरोपी म्यूल खाते उपलब्ध कराते थे। चीन में बैठे ठगों के टेलीग्राम चैनल से जुड़े साइबर ठग गिरोह का पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर समेत चाचा-भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। विदेशी ठग चीन में बैठकर भारतीयों के वॉट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर एपीके फाइल (एंड्राइड पैकेज किट) भेजकर बैंक खाते खाली कर रहे थे। पकड़े गए ठग अपने विदेशी आकाओं को म्यूल बैंक खाते उपलब्ध करवा रहे थे। आरोपियों की पहचान रिलेशनशिप मैनेजर व बिहार के गया निवासी फ्रांशु कुमार, मेरठ के सरधना स्थित छुर गांव निवासी शौकिन व इसके भतीजे शाहरुख के रूप में हुई है। ढाई माह में इस गिरोह ने करीब 50 लोगों को अपना शिकार बनाते हुए एक करोड़ रुपये की ठगी की है। ठगी की रकम क्रिप्टोकरेंसी के जरिये चीन के ठगों को भेजी जा रही थी। पुलिस ने इनके पास से कई म्यूल बैंक खाते व एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि ठगी की रकम दिल्ली के मयूर विहार फेज-एक स्थित सिटी यूनियन बैंक के एक संदिग्ध बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज जितेंद्र मलिक के नेतृत्व में एसआई अमन, एएसआई महेश, कांस्टेबल सरिता की एक टीम बनाई गई।

महीने की शुरुआत या अंत कब करें म्युचुअल फंड में निवेश

शेयर बाजार की रोजाना उठापटक के बीच म्यूचुअल फंड में सिप निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। हालांकि कई निवेशक इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सिप की तारीख महीने की शुरुआत या मध्य उनके रिटर्न को कितना प्रभावित करती है। मार्च 2015 से मार्च 2025 तक के 10 वर्षों के आंकड़ों पर एक विशेष स्टडी की गई। इसमें एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। इसमें महीने की अलग-अलग तारीखों पर किए गए सिप निवेश के रिटर्न की तुलना की गई। स्टडी के परिणाम बताते हैं कि औसत रिटर्न 13.07 प्रतिशत से 13.26 प्रतिशत के बीच रहा, यानी अंतर बेहद मामूली है। यदि कोई निवेशक हर महीने 2000 की सिप करता है, तो 10 साल बाद अलग-अलग तारीखों के आधार पर कुल रकम में केवल लगभग 6,000 का अंतर सामने आया। यह संकेत देता है कि लंबी अवधि के निवेश में तारीख का चुनाव निर्णायक भूमिका नहीं निभाता।

असली फर्क किन बातों से पड़ता है?-विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश की सफलता तारीख से ज्यादा इन कारकों पर निर्भर करती है--

-सही फंड का चयन

जैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप

-निवेश की अवधि

जितनी लंबी अवधि, उतना बेहतर संभावित रिटर्न

-नियमित निवेश और अनुशासन बनाए रखना

-हर साल निवेश राशि में धीरे-धीरे बढ़ोतरी (स्टेप-अप)

-बाजार में गिरावट के दौरान भी निवेश जारी रखना

-शॉर्ट टर्म में असर, लॉन्ग टर्म में संतुलन

निवेश की तारीख कैसे चुनें?

विश्लेषण यह भी स्पष्ट करता है कि स्ढ्ढक्की तारीख बाजार की टाइमिंग के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैश फ्लो के अनुसार तय करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सैलरी महीने की शुरुआत में आती है तो उसी समय स्ढ्ढक्क सेट करना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। इससे न केवल खाते में पर्याप्त बैलेंस बना रहता है, बल्कि किस्त छूटने या पेनल्टी लगने की संभावना भी खत्म हो जाती है।

थोक महंगाई दर मार्च में 3.88 प्रतिशत रही, गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं-थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर मार्च में बढ़कर 3.88 प्रतिशत हो गई है, जो कि फरवरी में 2.13 प्रतिशत थी। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई। मार्च में थोक महंगाई दर में वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, गैर-खाद्य वस्तुओं, बुनियादी धातुओं के विनिर्माण और खाद्य पदार्थों आदि की कीमतों में उछाल के कारण हुई है।आहार

आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में मार्च में फरवरी के मुकाबले 4.13 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। खनिज तेल की कीमतों में मार्च में पिछले महीने के मुकाबले 8.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बिजली की कीमत में मार्च में 5.07 प्रतिशत की कमी देखने को मिली। मंत्रालय ने बताया कि 22 विनिर्माण समूह में से 16 की कीमतों में मार्च में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं, छह में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, थोक खाद्य महंगाई दर मार्च में 1.85 प्रतिशत पर रही है। यह फरवरी में भी इस स्तर पर थी। इससे पहले, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए थे और यह मार्च में सालाना आधार पर 3.4 प्रतिशत रही है, इसमें क्रमिक आधार पर 0.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फरवरी में यह 3.21 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने कहा कि मार्च में ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 3.63 प्रतिशत और शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 3.11 प्रतिशत रही है। खाद्य महंगाई दर मार्च में 3.87 प्रतिशत रही है और फरवरी में यह 3.47 प्रतिशत थी। मार्च में ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 3.96 प्रतिशत रही है और शहरी इलाकों में यह 3.71 प्रतिशत थी।

तेल दामों में अभी स्थिरता- मध्य पूर्व में तनाव के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में ईंधन की कीमतों में 42 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पाकिस्तान में 28 फरवरी को पेट्रोल का दाम 266.17 प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया और डीजल का दाम 280.86 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया था। वहीं, 16 अप्रैल को पेट्रोल का दाम 366.58 रुपए बढ़कर प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया और डीजल का दाम बढ़कर 385.54 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया हो गया है। यह दिखाता है कि समीक्षा अवधि के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 37.74 प्रतिशत और डीजल की कीमत में 37.27 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नेपाल में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते एक महीने में चार बार कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पूरे दक्षिण एशिया में नेपाल में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत 219 नेपाली रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं, डीजल 207 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं, 28 फरवरी को नेपाल में पेट्रोल का दाम 154 नेपाली रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 156 नेपाली रुपए प्रति लीटर था।

यह दिखाता है कि समीक्षा अवधि के दौरान नेपाल में पेट्रोल का दाम 42.20 प्रतिशत और 32.59 प्रतिशत बढ़ गया है। भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम उभोक्ताओं को बचाने के लिए मोदी सरकार ने भार स्वयं वहन करने का फैसला लिया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ऑफर मिलने पर जानिए नियम

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरी काफी अच्छी मानी जाती है। अच्छी सैलरी के साथ कई तरह की सुख-सुविधाएं भी मिलती हैं हालांकि उससे बेहतर ऑफर मिल जाने पर लोग वहां की नौकरी भी छोड़ देते हैं। किसी कंपनी से रिजाइन करने के बाद एंप्लॉई को नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। नोटिस पीरियड नियम कंपनी और देश के श्रम कानूनों पर निर्भर करते हैं। ये नियम कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के लिए लागू हो सकते हैं। इन नियमों के बारे में करार में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। आमतौर पर हर कंपनी अपने नियम खुद सेट करती है पर कुछ नियम लगभग हर रजिस्टर्ड कंपनी पर लागू होते हैं. जानिए नोटिस पीरियड के कुछ ऐसे सामान्य नियम, जो सभी कंपनियों पर लागू हैं.

अवधि- नोटिस पीरियड की अवधि आमतौर पर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक हो सकती है। यह आपके पद, अनुभव और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

उदाहरण- जूनियर लेवल के लिए 30 दिन, सीनियर लेवल के लिए 60 दिन.

लिखित सूचना: नौकरी छोड़ने की सूचना आमतौर पर लिखित रूप में (ईमेल या रिजाइनेशन लेटर) के जरिये देनी होती है। इसमें नोटिस पीरियड शुरू होने की तारीख और लास्ट वर्किंग डे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इससे बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

काम करना- नोटिस पीरियड के दौरान सामान्य रूप से काम करना पड़ता है, जब तक कि कंपनी आपको पहले रिलीव न कर दे। वहीं कुछ मामलों में, कंपनी एक विकल्प दे सकती है, जहां आपको काम नहीं करना पड़ता पर आप तकनीकी रूप से अभी भी कर्मचारी रहते हैं.

सैलरी-नोटिस पीरियड के दौरान भी पूरी सैलरी मिलती है। अगर आप नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी आपसे उस अवधि की सैलरी वापस मांग सकती है। इसे आमतौर पर नोटिस पीरियड बाईआउट कहा जाता है.

कानूनी बाध्यता-भारत जैसे देशों में, श्रम कानून नोटिस पीरियड को नियंत्रित करते हैं। अगर अनुबंध में लिखा है तो उसे मानना जरूरी होता है। यह बात कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों पर लागू होती है। इसमें सामान्य रुप से नोटिस पीरियड एक माह का होता है।

आईआईटी जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से शुरु होगी

इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी) जेईई एडवांस परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे छात्र ध्यान दे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु रही है। गयी है। ये रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 मई, 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 4 मई, 2026 है. इसके बाद 11 मई, 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि परीक्षा 17 मई, 2026 को होगी। . इसका रिजल्ट 1 जून, 2026 को जारी कर दिया जाएगा।

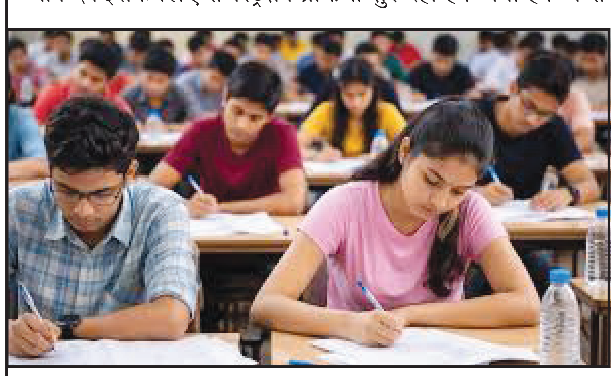

इस परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने जेईई मेंस में तय कट-ऑफ मार्क्स हासिल किए हों। परीक्षा दूसरा और सबसे अहम चरण मानी जाती है, जिसमें केवल चुने हुए उम्मीदवारों को ही बैठने का मौका मिलता है.

उम्र-सामान्य , ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स की जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद की होनी चाहिए. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, यानी उनकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1996 या उसके बाद की होनी चाहिए.

आवेदन फीस -आवेदन फीस कैंडिडेट्स की केटेगरी के अनुसार तय की गई है. सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस 3200 रुपये रखी गई है. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 1600 रुपये है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या दूसरे उपलब्ध ऑप्शंस के जरिए किया जा सकता है।

फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें ये डॉक्युमेंट्स--अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स को कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स पहले से तैयार रखने चाहिए. इसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी शामिल है। इसके साथ ही ओबीसी-एनसीएल या ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को ध्यान रखना होगा कि उनका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद जारी हुआ हो।

12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करने का चलन बढ़ा

12वीं के बाद अगर आप वकालत लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीबीए+एलएलबी या बीसीए+एलएलबी जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशंस है। अब इन दो कोर्सेस के साथ एलएलबी की डिग्री भी ले सकते हैं।समय के साथ ही करियर विकल्प भी बदलते जा रहे हैं। अब छात्रों के पास एक ही फील्ड में कई करियर विकल्प होते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेस का चलन बढ़ा है। इन कोर्सेस में दो अलग-अलग डिग्रियों की पढ़ाई एक साथ होती है। कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट को दोनों को मिलाकर एक डिग्री दी जाती है। अगर आप बीबीए या बीसीए के साथ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जानिए कुछ बेस्ट ऑप्शन.

बीबीए, बीसीए लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच साल)

बीबीए एलएलबी - इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई एक साथ होती है। इसमें बिजनेस से जुड़े विषयों (मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर) के साथ-साथ कानून के मूल सिद्धांत (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ) पढ़ाए जाते हैं।

बीबीए और बीसीए के बाद लॉ (3 साल का एलएलबी)

बीबीए या बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो पहले बिजनेस या टेक्नोलॉजी में बेस बनाना चाहते हैं और फिर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं।

बीबीए के बाद- कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ में विशेषज्ञता ले सकते हैं। बीसीए के बाद- साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में करियर बना सकते हैं। **स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स**

बीबीए/बीसीए के साथ या बाद में आप लॉ से जुड़े शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे-

1- साइबर लॉ (बीसीए के लिए)

2- कॉर्पोरेट लॉ (बीबीए के लिए)

3- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर)

यह कोर्स 6 महीने से 1 साल के हो सकते हैं और ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं.

लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन इस प्रकार मिलेगा

बीबीए एलएलबी के लिए

एलिजिबिलिटी- 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से), कम से कम 45-50 फीसदी अंकों के साथ. कुछ कॉलेज में मैथ्स होना अनिवार्य हो सकता है.

प्रवेश परीक्षा -कलेट टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए.

एआई एलईटी-एलऐट प्राइवेट लॉ कॉलेज के लिए.

एमसी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए. प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही कालेजों में प्रवेश मिलेगा।

पीजीआईएमईआर में सीनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन करें

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजी आई एमईआर) में पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में सीनियर रिसर्च फेलो सहित कुल 3 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये हैं। पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़ ने जिन 3 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें सीनियर रिसर्च फेलो, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट-I और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट-I के 1-1 पद शामिल है।

योग्यता -अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी एएनआरएफ, आईसीएमआर/पीजीआईएमईआर के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बेसिक साइंस में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन/मास्टर डिग्री के साथ अनुसंधान में अनुभव; 10वीं के साथ 2 वर्ष का अनुभव या 3 वर्षों की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।

आयु -उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पद अनुसार 30 से 35 साल के बीच निर्धारित की गई है, जिसकी गणना इंटरव्यू के तारीख के आधार पर की जाएगी।

चयन -वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से विभागाध्यक्ष, मुख स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के पते पर किया जाएगा।

भारत की शक्ति एवं वैश्विक परिदृश्य: स्किल्ड वर्कफोर्स बड़ी ताकत

– किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर भारत आज केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है,बल्कि यह विश्व के लिए आशा,स्थिरता और अवसरों का केंद्र बन चुका है। भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे केवल एक राष्ट्र की उपलब्धि कहना कम होगा।यह 21वीं सदी के उस नए युग की शुरुआत है यह स्वतंत्रता के 75 से अधिक वर्षों की यात्रा में भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि, लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आत्मा है। इसके साथ ही,भारत की जनसांख्यिकी और विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स ने उसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां से वह न केवल अपने नागरिकों के भविष्य को संवार सकता है,बल्कि पूरे विश्व के विकास की दिशा भी तय कर सकता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र से, यह लेख तीन मुख्यस्तंभों, लोकतंत्र की शक्ति, जनसांख्यिकीय लाभ और स्किल्ड वर्कफोर्स की क्षमता पर आधारित है, जिनकी वजह से भारत और उसके वैश्विक साझेदारों के बीच हर रिश्ते को विन-विन सिचुएशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साथियों बात अगर हम भारत की पहली सबसे बड़ी ताकत की करें तो,भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।1950 में संविधान लागू होने के बाद से आज तक भारत ने चुनावों के जरिए सत्ता परिवर्तन, नीति निर्माण और नागरिक अधिकारों को जिस मजबूती से कायम रखा है, वह विश्व के लिए उदाहरण है। लोकतंत्र का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक भागीदारी, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और पारदर्शी शासन की नींव पर खड़ा है। विविधता में एकता इसका सबसे बड़ा परिचायक है, जहां 22 आधिकारिक भाषाएँ, हजारों बोलियाँ, सैकड़ों धर्म-संप्रदाय और अलग-अलग संस्कृतियाँ होने के बावजूद लोग लोकतांत्रिक रूप से एकजुट रहते हैं। भारत का लोकतंत्र वैश्विक कंपनियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है क्योंकि वे जानती हैं कि यहां नीतियाँ पारदर्शी हैं, कानून का शासन है और निवेशकों के हितों की रक्षा की जाती है।दुनिया के कई हिस्सों में अधिनायकवाद और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है। अफ्रीकी और

एशियाई देशों में सत्ता परिवर्तन अक्सर हिंसा और अराजकता का कारण बनते हैं।इसके विपरीत भारत ने अपने लोकतांत्रिक ढांचे से स्थिरता का माहौल तैयार किया है। यही कारण है कि विश्व की बड़ी कंपनियाँ भारत को सेफ़ हैवन के रूप में देखती हैं। चीन या रूस जैसे देशों में निवेश करने पर राजनीतिक जोखिम अधिक होता है, जबकि भारत में लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ स्थिर रहें और निवेश सुरक्षित रहे। यह लोकतंत्र की वही शक्ति है जो भारत को अलग पहचान दिलाती है। साथियों बात अगर हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताक़त की करें तो वह है उसकी जनसांख्यिकी।वर्तमान समय में भारत की आबादी लगभग 1.43 अरब है और इसमें से 65 पेर्सेंट से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में आते हैं। यह स्थिति भारत को दुनियाँ की सबसे युवा आबादी वाला देश बनाती है। युवा आबादी किसी भी राष्ट्र के लिए ऊर्जा, नवाचार और विकास का प्रतीक होती है। जब यूरोप और जापान जैसे विकसित देश बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं, तब भारत के पास एक ऐसा डेमोग्राफिक एडवांटेज है जो उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बना सकता है।भारत की युवा पीढ़ी तकनीक अपनाने में सबसे आगे है। वे न केवल नई तकनीकों को अपनाते हैं बल्कि स्टार्टअप्स और उद्यमिता की ओर भी बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।मेक इन इंडिया,स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएँ इसी युवा ऊर्जा का परिणाम हैं। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को न केवल घरेलू विकास की दिशा में मजबूत बना रहा है बल्कि विश्व के लिए भी अवसर पैदा कर रहा है।भारत की यह जनसांख्यिकी वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। भारत हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजमेंट प्रोफेशनल तैयार करता है। यह वर्कफोर्स पूरी दुनिया की ज़रूरतें पूरी करता है। भारतीय पेशेवर आज अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका तक अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यह युवा आबादी उपभोक्ता बाजार के रूप में भी बेहद आकर्षक है। युवा वर्ग नई तकनीकों, डिजिटल सेवाओं और उपभोक्ता उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है। यही कारण है कि वैश्विक कंपनियाँ भारत को भविष्य का सबसे बड़ा बाजार मानती हैं। साथियों बात अगर हम भारत की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की करें तो वह है उसका विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स। भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पूल है।आईटी, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, रिसर्च, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीयों ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर वैश्विक आईटी हब के रूप में उभर चुके हैं। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिकी सिलिकॉन वैली की कंपनियों के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। हेल्थकेयर के क्षेत्र में भारतीय डॉक्टर और नर्स पूरी दुनिया में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यह साफ दिखाई दिया कि भारतीय मेडिकल प्रोफेशनल्स की क्षमता कितनी विशाल है।मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया अभियान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है और भारत में उत्पादन का माहौल तैयार किया है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसने लाखों रोजगार पैदा किए हैं। यह स्किल्ड वर्कफोर्स केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक नवाचार और विकास के लिए भी अहम है।साथियों बातें कर हम इन तीनों कारकों,लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और स्किल्ड वर्कफोर्स,का संगम भारत को विश्व की बड़ी कंपनियों और सरकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की करें तो, जब कंपनियाँ भारत में निवेश करती हैं तो उन्हें स्थिर राजनीतिक माहौल, विशाल उपभोक्ता आधार और प्रतिभाशाली मानव संसाधन तीनों एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और टेस्ला जैसी कंपनियाँ भारत को भविष्य का हब मान रही हैं।भारत और उसके वैश्विक साझेदारों के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। भारत को रोजगार, तकनीक और निवेश मिलता है,जबकि कंपनियों को लागत में कमी, स्थिर वातावरण और विशाल बाजार तक पहुंच मिलती है।

भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया जॉब एक्सपो का सफल आयोजन

बाबैन, 17 अप्रैल (राजेश कुमार) : भारत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा जॉब एक्सपो 2026 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया, जिसने विद्यार्थियों को रोजगार के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित किया। यह कार्यक्रम पूर्व सांसद एवं संस्थान के अध्यक्ष प्रो. कैलाशो सैनी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। संस्थान के चेयरमैन ओम नाथ सैनी, वाइस चेयरमैन भारत सैनी तथा डायरेक्टर रुबेल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जॉब एक्सपो में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों एवं संस्थानों ने भाग लेकर विद्यार्थियों को अपने करियर को नई दिशा देने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर लगभग 200 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया। फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लेबोरेट फार्मास्यूटिकल, धानुका फार्मास्यूटिकल्स, बायोमेक्स बायोटेक्निक प्रा. लि., बायोफील्ड फार्मा, ओम साई हेल्थकेयर,

उजाला सिग्नस हॉस्पिटल तथा पार्क हॉस्पिटल जैसी प्रमुख संस्थाओं ने साक्षात्कार आयोजित किए। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम, जी एंड एम कंसल्टेंट, ब्रिल अटॉर्नी, देसवाल एसोसिएट, एक्सिस बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस आयोजन ने न केवल विद्यार्थियों के लिए रोजगार के द्वार खोले, बल्कि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उद्योग जगत के साथ मजबूत संबंधों को भी उजागर किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में डॉ. लवकेश भाटिया (प्राचार्य, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी), डॉ. अनिल नागर (प्राचार्य, भारत कॉलेज ऑफ लॉ) तथा डॉ. मोनिका शर्मा (समन्वयक, III सेल) सहित समस्त स्टाफ सदस्यों का विशेष योगदान रहा। उनकी मेहनत, समर्पण और समन्वय से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संस्थान प्रबंधन ने सभी प्रतिभागी कंपनियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।

जनगणना पोर्टल पर आमजन अपनी व अपने परिवार की गणना स्वयं करके जिम्मेदार नागरिक बने : सतपाल पसरीचा

असंध, 17 अप्रैल (दलसिंह मान) : जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है इसी कड़ी में असंध उपमंडल के चार्ज ऑफिसर तहसीलदार नवजीत कौर की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर के दौरान असंध ब्लॉक के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए फील्ड ट्रेनर सतपाल पसरीचा ने आमजन से एक विशेष अपील करते हुए कहा कि है जनगणना 2026-2027 देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण डाटाबेस तैयार करेगी इस बार नागरिक जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने मकान की गणना स्वयं कर सकते हैं। सब गणना का यह विशेष चरण 16 अप्रैल से शुरू होकर 30

अप्रैल तक चलेगा। सतपाल पसरिचा ने बताया कि पोर्टल पर नागरिक अपनी जानकारी भर सकते हैं जवाब ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं उन्होंने कहा यह देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्व- गणना से मई महीने में होने वाली भौतिक मकान गणना में लग समय और और सरकारी संसाधनों की भी बचत होगी। आमजन की पहल देश के नियोजन में एक बड़ा योगदान देगी।

एनएच-44 पर कूड़े का काला धब्बा, सुभाष चंद्र की सख्ती से मचा हड़कंप, मौके पर ही शुरू हुआ सफाई अभियान

घरौंड़ा, 17 अप्रैल (नरेंद्र लाठर) : नेशनल हाईवे-44 की सर्विस लेन पर वीर राइस मिल से घरौंडा टोल तक पसरे कूड़े के ढेर ने आखिरकार प्रशासन की नींद तोड़ दी। स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने आज मौके पर पहुंचकर हालात देखे तो अधिकारियों की लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई—और यहीं से शुरू हुआ एक्शन।

जैसे ही सुभाष चंद्र को लोगों की परेशानी का पता चला, उन्होंने बिना देरी किए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर तलब कर लिया। नगर पालिका, नेशनल हाईवे विभाग और मार्केट कमेटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई।

कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए सफाई

निरीक्षण के दौरान सुभाष चंद्र का तेवर बेहद सख्त नजर आया। उन्होंने साफ कहा कि स्वच्छ भारत मिशन केवल फाइलों में नहीं चल सकता—सड़क पर गंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है।

फटकार के बाद तुरंत हरकत, शुरू हुआ सफाई अभियान

जैसे ही वाइस चेयरमैन ने सख्ती दिखाई, सफाई एजेंसी और कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जेसीबी और सफाई टीमों ने मौके पर ही कूड़ा उठाना शुरू कर दिया और पूरे इलाके को साफ करने का काम तेजी से चलाया गया।

लोगों ने कहा—ऐसे ही चाहिए चएक्शन वाला प्रशासन

स्थानीय निवासियों ने इस त्वरित कार्रवाई की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि अगर इसी तरह अधिकारी मौके पर जवाबदेह बनते रहें, तो शहर को साफ रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई शराब को किया नष्ट

यमुनानगर, 17 अप्रैल (दिनेश कुमार) : पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के कुशल मार्गदर्शन में थानों में पड़े माल मुकदमों का निपटारा करवा कर नष्ट किया जा रहा है। इसी कड़ी में निपटान मामलों की शराब को नष्ट किया गया है। यह कार्रवाई डी.एस.पी. मुख्यालय कवलजीत सिंह, थाना प्रबंधक निरीक्षक कमलजीत सिंह व एक्साईज इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह गोयत की देखरेख में हुई। जानकारी देते हुए डीएसपी कवलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबंधक थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जिस भी थाना का माल मुकदमा पेंडिंग है उन सभी का माननीय अदालत के माध्यम से निपटारा करवा कर माल मुकदमों को नष्ट करवाया जाए ताकि थानों की साफ-सफाई को भी दुरुस्त करवाया जा सके। इसी कड़ी में वीरवार को आबकारी अधिनियम के तहत पकड़ी गई कुल 352 बोतल देसी शराब, 1060 बोतल अंग्रेजी शराब को थाना सदर यमुनानगर के पिछले प्रांगण में बुल्डोजर के माध्यम से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये निर्णय पुलिस कर्मचारियों की स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। पुरानी शराब के कारण मालखाना में बदबू हो जाती है, वहीं मालखाना से अन्य माल मुकदमा निकालने में भी परेशानी होती है।

खरीद एजेंसियों ने अब तक खरीदी 324361 मीट्रिक टन गेहूं : विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र, 17 अप्रैल (सुदेश कुमार) : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के खरीद केन्द्रों व मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य खाद्य आपूर्ति, हैफेड तथा हरियाणा वेयर हाउस एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। इन तीनों एजेंसियों ने 16 अप्रैल को देर सायं तक 324361 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का कार्य पूरा कर लिया है। इस सीजन में गेहूं का 2585 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अहम पहलू यह है कि जिले में 78987 एमटी गेहूं का उठान कार्य पूरा किया गया है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद करने के लिए 29 खरीद केन्द्र व मंडिया स्थापित की गई है। इन मंडियों से खाद्य आपूर्ति, हैफेड, एफसीआई और हरियाणा वेयर हाउस कार्पोरेशन की तरफ गेहूं की खरीद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन में खाद्य आपूर्ति एजेंसी द्वारा अमीन में 1006 एमटी, बाबैन मंडी में 16870 एमटी, बौर सैंदा में 3184 एमटी, गुमथला गढु में 14281 एमटी, ईशहाक में 3029 एमटी, इस्माइलाबाद मंडी में 23490 एमटी, झांसा मंडी में 6353 एमटी, कराह साहब में 5986 एमटी, थानेसर मंडी में 39201 एमटी, लाडवा मंडी से 31646 एमटी, नलवी में 550 एमटी, नीमवाला में 4261 एमटी, पिहोवा मंडी में 21828 एमटी, पिहोवा एक्टेंशन मंडी में 7486 एमटी, पिपली मंडी से 7902 एमटी, शाहबाद से 19099 एमटी, थाना में 2245 एमटी, ठोल मंडी से 9247 एमटी गेहूं खरीद गया है। उन्होंने कहा कि हैफेड द्वारा अजराना कला में 2434 एमटी, बोधनी मंडी में 2600 एमटी, चढुनी जाटान मंडी में 1622 एमटी गेहूं, इस्माईलाबाद मंडी से 16179 एमटी, झांसा मंडी में 576 एमटी, किरमच में 1443 एमटी, थानेसर 22246, लाडवा मंडी में 6231 एमटी, लुखी में 2504 एमटी, मलिक पुर में 4795 एमटी, पिहोवा मंडी में 15366 एमटी गेहूं, पिहोवा एक्सटेंशन में 6106 एमटी, पिपली मंडी में 6631 एमटी गेहूं, शाहबाद मंडी में 9576 एमटी गेहूं खरीद कार्य पूरा किया गया है। इसी तरह हरियाणा वेयरहाउस द्वारा बारना में 2255 एमटी, बोधनी में 1690 एमटी, ठोल में 4443 एमटी गेहूं खरीद कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि उठान कार्य पर विशेष फोकस रखा जाए ताकि व्यापारियों और किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के आदेश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए व्यवस्था और प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। ऐसे में किसान सहभागी बनते हुए खरीद कार्य में अपना योगदान दें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी गेहूं की फसल को अच्छी तरह से सुखाकर एवं साफ करके मंडी में लाएं।

अवैध देसी कट्टे व दो जिंदा कारतूस सहित आरोपी काबू

यमुनानगर, 17 अप्रैल (दिनेश कुमार) : पुलिस की अपराध शाखा -1 की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इन्चार्ज राजकुमार ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक बिलासपुर के पास अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। इस सूचना के आधार पर एएसआई जगतार, अमरजीत प्रमोद पुनीत और सुशील की टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत मौके पर जाकर एक युवक को काबू किया। तलाशी लेने पर जिसके पास एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। जिसकी पहचान भगवानपुर निवासी अमित कुमार पुत्र भोपाल सिंह के नाम से हुई। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज

कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और कहीं वह किसी आपराधिक गिरोह से तो नहीं जुड़ा हुआ। इंचार्ज राजकुमार ने कहा कि अवैध हथियार समाज में अपराध और असुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। जिला पुलिस इस तरह के अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी को अवैध हथियार रखने या उनकी खरीद-फरोख्त से संबंधित कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। पुलिस का यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा ताकि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

हर विकास कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी : सुमन बहमनी

मेयर व विधायक ने किया रेवेन्यू रास्ते का शिलान्यास, 15.04 लाख से होगा निर्माण

यमुनानगर, 17 अप्रैल (दिनेश कुमार) : मेयर सुमन बहमनी व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने शुक्रवार को वार्ड 19 के विष्णु नगर में 15.04 लाख की लागत से बनने वाले राजा गार्डन रेवेन्यू रास्ते का शिलान्यास किया। उन्होंने पार्षद हरजीत सिंह आनंद के साथ नारियल फोड़कर रेवेन्यू रास्ते के नवनिर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान मेयर व विधायक ने क्षेत्र के लोगों को इस विकास कार्य की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना नगर निगम की प्राथमिकता है। रेवेन्यू रास्ते के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा।

मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए

कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और तय समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले हर कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर शहर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे, जिससे शहर की आधारभूत संरचना और मजबूत होगी। पार्षद हरजीत सिंह आनंद ने मेयर व विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस रास्ते के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। मौके पर नगर निगम के सहायक अभियंता राजेश शर्मा, कनिष्ठ अभियंता अरविंद कुमार, पूजा मोंगा, विनेश मनकट, नितिन आनंद, शालू, डिंपल, रवि नीला, जतिंदर, विजय धीमान, केवल, कमल, प्रिंस आदि मौजूद रहें।

अंगदान जरूरतमंदों के लिए वरदान : डॉ. नीना

करनाल, 17 अप्रैल (संदीप रोहिला) : बी.आर.एम. कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मोहन फाउंडेशन की एम्बेसडर डॉ. नीना ने बी.एड. एवं डी.एल.एड. के विद्यार्थियों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अंगदान मृत्यु के बाद किया जाने वाला सबसे बड़ा दान है। जिससे कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। डॉ. नीना ने बताया कि इंसान मरने के बाद भी अपने अंगों के माध्यम से दूसरों के शरीर में जीवित रह सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में हर वर्ष हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि समय पर अंगदाता नहीं मिल पाते। ऐसे में समाज को अंगदान के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि दान करो आंखों के मोती, ताकि किसी के जीवन में फिर से रोशनी आ सके। डॉ. नीना ने यह भी बताया कि ब्रेन डेथ के बाद एक व्यक्ति अपने अंगों के जरिए 9 लोगों को जीवनदान दे सकता है और उनके परिवारों में खुशियां ला सकता है। उन्होंने अंगदान के लिए संकल्प लेने हेतु टोल फ्री नं. 18001037100 पर पंजीकरण करने की जानकारी भी दी। कॉलेज के डायरेक्टर कृष्ण शर्मा ने कहा कि आज के समय में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य के लिए आगे आएं। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पायल काजल सहित स्टाफ सदस्य डॉ. नरेंद्र, डॉ. राजकुमार, डॉ. रीना, संजू, प्रीति, पवन, कुलदीप और सपना उपस्थित रहे।

पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए जिला के प्रत्येक गांव में मुहैया कराई जाए किट : एसडीएम

सोनीपत, 17 अप्रैल (ब्यूरो) : एसडीएम प्रवेश कादियान की अध्यक्षता में लघु सचिवालय, सोनीपत में जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 13 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई व एसडीएम के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। नल द्वारा जिला के सभी गांव में पीने का पानी, पीने के पानी की गुणवत्ता, ग्रामीण स्तर पर कमेटी, जल अर्पण दिवस, बैंक अकाउंट खुलवाना, शिकायत निवारण केंद्र व अन्य विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम प्रवेश काद्यिान ने बैठक के दौरान पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी गांव में किट मुहैया करवाए। गांव में किट आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, सरकारी स्कूल, सरपंच व पंच को दी जाए। जिससे समय-समय पर ग्रामीण स्तर पर ही पानी की जांच की जा सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि ब्लॉक रिर्सोस कॉर्डिनेटर (बीआरसी) जिला के प्रत्येक गांव में सरपंच के सहयोग से ग्रामीणों को जल बचाव को लेकर जागरूक करें। उन्होंने बताया कि जिला में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत जल अर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों एवं समुदाय को हस्तांतरण किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन न होकर, सामुदायिक स्वामित्व और सहभागिता का प्रतीक है। इसके माध्यम से गांवों को जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन, संरक्षण एवं रखरखाव की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एसई दलबीर सिंह ने बताया कि कुल 318 ग्राम पंचायतों में से 18 गांवों की ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया जा चुका है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल अर्पण दिवस के अंतर्गत 8 मार्च को गांव ठरू (ब्लॉक सोनीपत) तथा 11 मार्च को गांव बिधलान (ब्लॉक खरखौदा)में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-180-5678 या व्हाट्सएप नम्बर 9041741800 पर शिकायत दे। उन्होंने बताया कि विभाग को प्राप्त होनी वाली शिकायतों का समाधान शिकायत निवारण केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। बैठक के दौरान पब्लिक हेल्थ से एक्सीईन गौतम कुमार, बीडीपीओ कथूरा पूनम चंदा व अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

एसडीएम प्रवेश काद्यिान की अध्यक्षता में हुई आईआईएचएम, गन्नौर से जुडे मुद्दों से संबंधित बैठक:- एसडीएम प्रवेश काद्यिान की अध्यक्षता में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, गन्नौर (आईआईएचएम) से जुडे मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संबंधित विभागों के साथ वाल्मीकि आश्रम, हनुमान मंदिर, पीर व श्मशान घाट के स्थानांतरण, टेहा गांव से जुड़े पानी के मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो शमशान घाट, व टेहा गांव से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कार्य करे। उन्होंने इस दौरान गन्नौर तहसीलदार ललिता को निर्देश दिए कि वो शमशान घाट से जुड़ी संबंधित जमीन की निशानदेही करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान एक्सीईन आईआईएचएम सुभाष चंद्र, एक्सीईन पंचायती राज कुलबीर सिंह, पब्लिक हेल्थ एक्सीईन गौतम कुमार व अन्य सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना दे रही महिलाओं को आर्थिक सहायता

करनाल, 17 अप्रैल (सुमन लता) : डी.सी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। डी.सी ने बताया कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में बकायादार (डिफॉल्टर) नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलायें स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत ऋण लेकर यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, परियोजना रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी जरूरी है।

जिन्हें फील्ड का पर्याप्त अनुभव नहीं, उन्हें भेजा रहा है फील्ड में, कर्मचारियों के लिए बन रहा जान का खतरा

घरौंडा, 17 अप्रैल (सतीश कुमार पंडित) : घरौंडा में हरियाणा बिजली वितरण निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने विभिन्न डिवीजनों के एएसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बिना अनुभव वाले कर्मचारियों को फील्ड में भेजा जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा के साथ-साथ बिजली व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष दिनेश राणा, सुनील हुड्डा, जिला सचिव सुमित मक्कड़, उपमंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह, उपमंडल उपाध्यक्ष अमित, सचिव सचिन पुनिया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने एएसडीओ के आदेशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असिस्टेंट लाइनमैन (एएलएम) को उनकी जॉइनिंग के तुरंत बाद ही शिफ्ट अटेंडेंट (एसए) के रूप में काम करने के निर्देश

दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें फील्ड का पर्याप्त अनुभव नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल अनुचित है बल्कि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि एएलएम को एसए पद पर भेजने का मामला अभी यूएचबीवीएन पंचकूला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विचाराधीन है, इसके बावजूद आदेश लागू करना मनमानी है। प्रदर्शनकारियों ने एचकेआरएन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि कच्चे कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों में लगाया जा रहा है, जबकि पक्के कर्मचारियों को दफ्तरों में बैठाया जा रहा है, जिससे विभाग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान सीजन के चरम पर ऐसे निर्णय विभागीय कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

30 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का भरें विवरण : विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र, 17 अप्रैल (सुदेश कुमार) : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जनगणना 2027 के पहले चरण में नागरिक स्वयं भी अपनी जनगणना कर सकेंगे। आमजन 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल एसई डॉट सीईएनयूएस डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से अपने परिवार का विवरण भर सकेंगे। स्व गणना के माध्यम से नागरिक अपनी जानकारी स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए है जो किसी कार्यवश दिनभर अपने घरों से दूर रहते हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जनगणना 2027 को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने स्वयं भी स्वगणना पोर्टल पर

जाकर अपना विवरण भरा। उन्होंने कहा कि यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का होगा। इसे 1 से 30 मई 2026 तक कराया जाना प्रस्तावित है। इस चरण के अंतर्गत गांवों एवं शहरों के आवासीय, गैर-आवासीय तथा सह-आवासीय भवनों की गणना की जाएगी। इसी प्रकार दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश एवं जनता के कल्याण के लिए नीतियों एवं योजनाएं बनाने के लिए अनिवार्य है। इसमें हर भवन हर व्यक्ति की गणना होना अनिवार्य है, क्योंकि यही आंकड़े विकसित भारत के निर्माण के लिए आधार बनेंगे। इसी के आधार पर शिक्षा, आवास एवं घरेलू, सुविधाएं प्रदान करना एवं अनेक कल्याणकारी योजनाएं सम्मिलित है। जनगणना में दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पूर्ण रूप से गोपनीय है। नागरिकों की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और नागरिक निसंकोच होकर अपनी जानकारी प्रगणक को दें और देश के विकास का हिस्सा बनें। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि स्व गणना की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है, जिसके लिए नागरिक गूगल पर सेल्फ एनुमरेशन टाईप करें और घर के मुखिया के नाम व मोबाइल से लॉग इन करें, जिससे एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस के बाद भाषा का चयन करें। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के साथ 14 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इसके बाद नागरिक गूगल मैप पर अपने राज्य, जिला व पिन कोड को डालते हुए अपने घर को मैप पर लोकेट करें। अपने घर की लोकेशन कंफर्म करते ही पहले चरण के सभी प्रश्न खुल जाएंगे। ये 27 प्रश्न मकान की स्थिति, घर में कुल लोगों की संख्या, घर के मुखिया की जानकारी, पेयजल का स्रोत, घर में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, कार का होना आदि के बारे में हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं।

इनका जवाब देने के बाद जब सबमिट करने पर मैसेज या ईमेल के द्वारा एक स्व गणना आईडी की प्राप्ति होगी, जोकि प्रगणक के घर आने पर, उसे देनी होगी। आईडी द्वारा सभी प्रश्नों का जवाब प्रगणक के पास आ जाएंगे और इसके सत्यापन के बाद वह इसे सबमिट कर देगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सभी सांसदों, विधायकों, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के सदस्य, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ब्लॉक समिति और उनके सदस्य, सभी पंच व सरपंच, सभी सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारी एवं सभी युवाओं, सभी किसानों, छोटे-बड़े सभी व्यापारी गण एवं सभी आम आदमी से अपील की कि वे अपनी गणना स्वयं भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस अवसर पर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र चौधरी, जिला संख्यक कोऑर्डिनेटर मंजू सहित संबंधित अधिकारियों उपस्थित रहे।

मानसून सीजन से पहले नालों की सफाई का कार्य करें पूरा : उपायुक्त प्रीति

यमुनानगर, 17 अप्रैल (दिनेश कुमार) : उपायुक्त प्रीति ने जिला सचिवालय के सभागार में मानसून सीजन के दौरान जिला के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रो के कैचमेंट एरिया में अधिक वर्षा होने की स्थिति में संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों एवं प्रबंधो के बारे में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली जिसमें संभावित बाढ़ से निपटने के उपायों बारे चर्चा की व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा के समय आपसी समन्वय से जानमाल की बेहतरीन सुरक्षा की जा सकती है। साहस और सूझबूझ के साथ-साथ दक्षता से अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी संभावित बाढ़ वाले स्थानों को चिन्हित कर लें और सुदृढ़ व्यवस्था करे। उपायुक्त ने कार्यकारी अभियंता नगर निगम व कार्यकारी अभियंता पब्लिक हैल्थ विभाग को निर्देश दिए कि नालों और सिवरेज की सफाई के लिए एक्शन प्लान बनाकर नाले और नालियों की सफाई करवाएं, 15 मई 2026 तक सभी कार्य पूरे करवाएं। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिए कि बीडीपीओ के माध्यम से गांवों के तालाबों व अमृत

सरोवरों की सफाई करवाना सुनिश्चित करें जिससे बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लों न हो। उपायुक्त प्रीति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ के दौरान स्थिति से निपटने के लिए नौकाओं एवं गोताखोरों को संसाधनों सहित मुस्तैद रखें। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोमनदी, पथराला नदी, यमुनानदी सहित जरूरत की जगहों पर ठोकरो व तटबंधों की सुरक्षा पुख्ता करें। समय रहते नालों की सफाई का कार्य कर लें और यदि सड़कों एवं आने जाने वाले रास्तों में कोई गड्ढा वगैरह है तो उसे तुरन्त बन्द किया जाए। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग पानी की निकासी के लिए पम्प तैयार रखें। उपायुक्त ने कहा कि सिचांई एवं जल संसाधन विभाग, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति अभियांत्रिकी विभाग हर तरह से पूरी तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि सिचांई विभाग कॉम्यूनिकेशन सिस्टम सही ढंग से तैयार करें ताकि लोगों को संभावित बाढ़ के खतरों की पहले से ही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग), मार्किटिंग बोर्ड अपनी-अपनी सड़कों की पुलियों व पुलो के कलवट की सफाई तुरंत करवा लें। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अपने-अपने विभागों से संबंधित बाढ़ बचाव कार्यों एवं प्रबंधो को 15 मई तक हर हालत में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ, व्यासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम नरेन्द्र कुमार, नगराधीश पीयूष गुप्ता, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता प्रवीण गुप्ता, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता राहिल सैनी व विजय गर्ग, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता दिनेश गाबा, नगर निगम के सहायक अभियंता मृणाल जायसवाल सहित सभी विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

किसान फसलों का बच्चे की तरह ध्यान रखता है, भाजपा अन्नदाता को लाईनों में लगने को कर रही मजबूर : अभय चौटाला

शाहाबाद मारकंडा, 17 अप्रैल (रूबी) : गुरुवार देर सायं इंडियन नैशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला शाहाबाद नई अनाज मंडी में खोले गए किसान कष्ट निवारण केन्द्र पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचें। अभय चौटाला ने किसानों, आढ़तियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा को घेरते हुए अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा ऐसी सरकार है जब से सत्ता में आई है तब से अन्नदाता किसान सड़कों पर उतर-उतर कर अपने हकों की मांग करता है। चौटाला ने कहा कि भाजपा को केवल घोषणाएं करनी आती है जो धरातल पर कहीं नहीं होती, भाजपा बेतुके कानूनों को किसानों के सिर

मंढने का काम कर रही है। किसान दिन-रात खेतों में फसलों का बच्चे की तरह ध्यान रखता है, मंहगी खाद, बीज, यूरिया, दवाईयां खरीदता है लेकिन सरकार बदले में किसानों को पोर्टलों पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, बायॉमैट्रिक, गेट पास बनवाने के लिए घंटों लाईनों में लगाने का ईनाम दे रही है। एक तरफ तो किसान बेमौसमी बरसात के कारण खराब हुई फसलों को लेकर चिंता में है दूसरी तरफ भाजपा किसानों का दुख बाटने की बजाय उन्हें बेवजह परेशान कर रही है।

अभय चौटाला ने कहा कि सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर 50 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देकर किसानों को राहत प्रदान करे। चौ. अभय चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए खरीद नियम किसानों के हित में नहीं हैं और इससे उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और कानून जो ट्रैक्टर-ट्राली के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसका बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन अनिवार्य किया हुआ है, उसमें किसानों को बहुत समस्याएं आ रही है। चौटाला ने कहा कि किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए मंडियों में आते हैं, लेकिन उन पर अनावश्यक और कठोर शर्तें थोपी जा रही हैं। भाजपा की बेतुकी शर्तें किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। चौटाला ने कहा कि पहले टैंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण गेहूं का उठान प्रभावित हो रहा था।

इस तरह की व्यवस्था से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी फसल समय पर मंडियों से नहीं उठाई जा रही। यदि जल्द ही गेहूं का उठान शुरू नहीं हुआ और बायोमैट्रिक सिस्टम को न रोका गया तो इनैलो अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी। इनैलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी, बुट्टा सिंह लुक्खी, महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष तनुजा, अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह बिट्टू कालड़ा ने भी किसानों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मंडी में पहुंचनें पर जिलाध्यक्ष जयपाल चढूनी, हल्काध्यक्ष सूबे सिंह त्यौड़ी, हल्का प्रभारी सूरजभान रत्नगढ़, अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान स्वर्णजीत सिंह बिट्टू कालड़ा सहित इनैलो कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी का शॉल ओढ़ाकर एवं फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पारस चढूनी, जसबीर त्यौड़ी, संत संभालखी, मदन गोपाल, रामचन्द्र ढोलामाजरा, अमित शर्मा, नरेंद्र खानपुर, गुरपिंदर भिंडर सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

गत दिवस तक जिले में हुई कुल 4 लाख 30 हजार 343 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद

गेहूं के अवशेषों में आग न लगाएं किसान : डीसी अपराजिता

कैथल, 17 अप्रैल (सुरेंद्र कुमार) : डीसी अपराजिता ने बताया कि जिला में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बुधवार तक कुल 4 लाख 30 हजार 343 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद गई है। जिले में गेहूं की कुल आवक में से एक लाख 47 हजार 447 मीट्रिक टन गेहूं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा, एक लाख 82 हजार 549 हैफेड द्वारा तथा एक लाख 347 मीट्रिक टन गेहूं हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदा गया है।

उन्होंने बताया कि अगोंध मंडी में 4752 मीट्रिक टन, अरनोली मंडी में 4253 मीट्रिक टन, बाबा लदाना में 14558 मीट्रिक टन, बडसिकरी खुर्द में 7484 मीट्रिक टन, बलबेहड़ा मंडी में 3049 मीट्रिक टन, बालू मंडी में 5908 मीट्रिक टन, बरटा मंडी में 6250 मीट्रिक टन, बाउपुर में 910 मीट्रिक टन, भागल में 3474 मीट्रिक टन, भुसला में 2556 मीट्रिक टन,चीका मंडी में 34258 मीट्रिक टन, चीका अतिरिक्त मंडी 50350 मीट्रिक टन, डीग मंडी में 2254 मीट्रिक टन,धनोरी में 6777 मीट्रिक टन, फर्श माजरा में 2008 मीट्रिक टन, गोहरा में 5792 मीट्रिक टन, गुहणा में 1577 मीट्रिक टन, हाबड़ी मंडी में 5059 मीट्रिक टन, जाखोली मंडी में 4176 मीट्रिक टन, कैलरम में 3739 मीट्रिक टन, कैथल पुरानी मंडी में 6706 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इसके तरह कैथल नई अनाज मंडी में 39914 मीट्रिक टन, कैथल अतिरिक्त नई अनाज मंडी में 47721 मीट्रिक टन, कलायत अनाज मंडी में 32246 मीट्रिक टन, कमहेड़ी में 1033 मीट्रिक टन, कांगथली में 6766 मीट्रिक टन, करोड़ा में 7676 मीट्रिक टन, क्योड़क मंडी में 3727 मीट्रिक टन, किठाना में 18224 मीट्रिक टन, पाडला में 4743 मीट्रिक टन, पाई में 10437 मीट्रिक टन, पूंडरी मंडी में 3931 मीट्रिक टन, राजौंद अनाज मंडी में 17925 मीट्रिक टन, रामथली मंडी में 13498 मीट्रिक टन, रसीना में 4959 मीट्रिक टन, सजूमा मंडी में 1814 मीट्रिक टन, सांगण में 5200 मीट्रिक टन, सेरधा में 5456 मीट्रिक टन, सीवन में 14243 मीट्रिक टन, सोलू माजरा साइलो में 14940 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे गेहूं अवशेषों में आग न लगाएं, क्योंकि इससे जान और माल काफी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है।

बराड़ा रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर थाना प्रभारी से की मुलाकात

शाहाबाद मारकंडा, 17 अप्रैल (रूबी) : बराड़ा रोड पर स्वर्ग आश्रम के बाहर अतिक्रमण हटाने को लेकर राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की

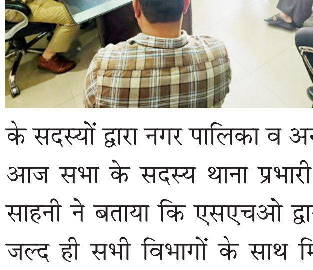

कार्यकारिणी ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। महासभा के शहरी प्रधान शुभम साहनी ने बताया कि स्वर्ग आश्रम के बाहर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जिसकी शिकायत महासभा के सदस्यों द्वारा नगर पालिका व अन्य संबंधित विभागों को की है और आज सभा के सदस्य थाना प्रभारी जगदीश कुमार से मिलने पहुंचे। साहनी ने बताया कि एसएचओ द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सभी विभागों के साथ मिलकर इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साहनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के उपरांत महासभा द्वारा यहां पर दीवार का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर संतोष कुकड़ेजा, गुलशन कवातरा, राघव दुआ, शिवम कवातरा, शिवम आदि मौजूद थे।

शिव शक्ति पब्लिक सी.से. स्कूल का परिणाम रहा शत प्रतिशत

मूनक, 17 अप्रैल (जय भगवान) : स्कूल के प्रांगण में दसवी कक्षा के छात्र छात्राओं को उनके बेहतर परीक्षा के परिणाम के लिए बच्चों का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। दसवीं कक्षा के 27 छात्र छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलक्ष्य में विद्यालय के प्रबंधक रणबीर सिंह व पवन कुमार, तथा प्रिंसिपल राजिन्द्र ने सभी विद्यार्थियों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। दसवी कक्षा में दीक्षा-92-1, तानिया 87, रुचि 871; पर्व-861 शिवम 85; अनुराग 85, राधव-841, अवनी 82- अर्थ- 80, यश, विकास 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस बेहतर रिजल्ट में सभी अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिसके लिए विद्यालय को प्रबंधक कमेटी द्वारा सभी स्टाफ की भरपूर सराहना की गई।

किसानों के खातों में गेहूं खरीद के भेजे 156 करोड़ 36 लाख 1 हजार 10 रुपए : विश्राम कुमार मीणा

कुरुक्षेत्र, 17 अप्रैल (सुदेश कुमार) : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले के किसानों के खातों में गेहूं खरीद के 156 करोड़ 36 लाख 1 हजार 10 रुपए भेजे जा चुके हैं। सरकार के निर्देशानुसार उठान के 48 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले की अनाज मंडियों में फूड सप्लाई एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड व हरियाणा वेयरहाउस द्वारा खरीद की जा रही है। अब तक जिले में 324461 एमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 78987 एमटी गेहूं की लिफ्ट हो चुकी है। लिफ्ट के साथ-साथ किसानों के खातों में गेहूं खरीद का पैसा 156 करोड़ 36 लाख 1 हजार 10 रुपए भेजा जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि फूड सप्लाई एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 217664 एमटी गेहूं की खरीद की गई है, इसमें से 54447 एमटी गेहूं की लिफ्ट की जा चुकी है और 112 करोड़ 86 लाख, 3 हजार 245 रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं। हैफेड द्वारा 98309 एमटी गेहूं की खरीद की गई है, इसमें से 23646 एमटी गेहूं की लिफ्ट की जा चुकी है और 42 करोड़ 54 लाख, 83 हजार 245 रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं। इसी तरह हरियाणा वेयर हाउस 8388 एमटी गेहूं की खरीद की गई है, इसमें से 894 एमटी गेहूं की लिफ्ट की जा चुकी है और 95 लाख 14 हजार 520 रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं।

वंचित सोसायटियां नए अधिनियम के तहत करवाएं पंजीकरण: सुनीता

कुरुक्षेत्र, 17 अप्रैल (सुदेश कुमार) : जिला रजिस्ट्रार फर्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र सुनीता ने कहा कि वंचित फर्म एवं समितियां नए अधिनियम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2024 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। जो समितियां सोसाइटी एक्ट 1860 में पंजीकृत हैं, उन सभी समितियों को नए एक्ट हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 (एचआरआरएस एक्ट 2012) के अंतर्गत नवीनीकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी समितियां पहले नवीनीकरण से वंचित रह गई थी वह विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा इंडस्ट्री डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर फर्म से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके व निर्धारित फीस जमा करवाकर अपना नवीनीकरण नए अधिनियम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2024 के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जो समितियां पहले से नए अधिनियम हरियाणा समितियां पंजीकरण एवं विनियम अधिनियम 2012 के तहत पंजीकृत हैं वह समितियां अपनी समिति के चुनाव व वार्षिक रिटर्नस आदि संबंधित दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें अन्यथा किसी भी देरी के लिए सोसायटी स्वयं जिम्मेवार होगी।

जलमाना सर्कल में रॉकेट लर्निंग टीम द्वारा टॉय मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन

असंध, 17 अप्रैल (दलसिह मान) : महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जलमाना सर्कल स्तर पर 8वें पोषण पखवाड़ा के तहत गांव जयसिंहपुरा में टॉय मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का आयोजन सीडीपीओ रजनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सुपरवाइजर शकुंतला, रॉकेट लर्निंग टीम से दीपिका एवं कविता तथा जलमाना सर्कल की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। वर्कशॉप के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने कम लागत एवं अपशिष्ट (वेस्ट) सामग्री से बहुत ही आकर्षक और उपयोगी टीएलएम (शिक्षण-अधिगम सामग्री) तैयार किए। इन टीएलएम के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, जिससे बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली भी बनाई गई, जिसके माध्यम से पोषण एवं स्वच्छता के संदेश को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में पोषण के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंत में यह संदेश दिया गया कि बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि उनकी रुचि बनी रहे और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।

बीवीएम इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 1 व 2 के छात्रों ने सीखी भाषा की अनोखी कला

बरनाला, 17 अप्रैल (बघेल सिंह धालीवाल) बीवीएम इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा1और2के विद्यार्थियों के लिए' शब्दों की दुनिया 'विषय पर एक अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और सृजनात्मक आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को भाषा की बारीकियों से परिचित कराया गया। इस विशेष सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को' शब्द लड़ी 'जैसे मनोरंजक तरीके से शब्दों का निर्माण और उनके प्रयोग का अभ्यास कराया गया, जिससे उनकी भाषा दक्षता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह और जिज्ञासा के साथ इस गतिविधि में भाग लिया। वे एक के बाद एक नए शब्द बनाते हुए भाषा के साथ खेलते नजर आए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों में भाषा के प्रति रुचि विकसित करना, उनकी शब्द-भंडार को बढ़ाना और अभिव्यक्ति कौशल को मजबूत बनाना था। शिक्षकों ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सही उच्चारण और शब्दों के सही प्रयोग की जानकारी भी दी, जिससे उनका भाषाई विकास और अधिक प्रभावी बन सके। विद्यालय के प्रबंधन ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में भाषा का विशेष महत्व होता है। विद्यालय के चेयरमैन श्री प्रमोद अरोड़ा जी ने कहा कि भाषा वह माध्यम है, जो बच्चों के विचारों को व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए प्रारंभ से ही भाषा पर मजबूत पकड़ होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती गीता अरोड़ा जी, श्री निखिल अरोड़ा जी एवं श्रीमती नेहुल अरोड़ा जी ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास बच्चों में सीखने की रुचि को बढ़ाते हैं और उन्हें रचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात विद्यालय की प्रिंसीपल श्रीमती मनिंदरजीत कौर धालीवाल जी ने अपने संबोधन में कहा कि शब्दों का सही ज्ञान बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें प्रभावी संवाद करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सत्र बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, बीवीएम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित' शब्दों की दुनिया 'सत्र नन्हे विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक अनुभव सिद्ध हुआ, जिसने उनके भाषा विकास को एक नई दिशा प्रदान की।

बूटा सिंह चौहान की वृहद आकार की पुस्तक का लोकार्पण किया गया

बरनाला, 17 अप्रैल (बघेल सिंह धालीवाल) आज सेंट बचनपुरी इंटरनेशनल स्कूल, पखो कला में पंजाबी के बहुमुखी लेखक एवं भारतीय साहित्य अकादमी, दिल्ली की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य बूटा सिंह चौहान की वृहद आकार की पुस्तक मेरे तीन नॉवेल - भाग दूसरा का लोकार्पण किया गया। यह रस्म स्कूल के संस्थापक रविंद्रजीत सिंह बिंदी द्वारा अदा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बूटा सिंह चौहान ने अपने उपन्यासों में मलवई जीवन को बेहद खूबसूरती से चित्रित किया है। उनके हर उपन्यास का विषय नया होता है और जीवन के बड़े सत्य पाठकों के सामने लाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। बूटा सिंह चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष इस श्रृंखला का पहला भाग प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनके तीन उपन्यास सत्त रंगियां चिड़ियां, साथ परिंदे और पता नहीं सी शामिल थे। इस दूसरे भाग में उजड़े कुएं का पानी, गेरू रंगे और लव प्रोजेक्ट शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अब तक वे दस उपन्यास लिख चुके हैं। बोलिकार रघवीर गिल कट्टू ने कहा कि चौहान साहित्य सृजन को समर्पित लेखक हैं। वे स्वयं निरंतर लेखन करते हैं और नए तथा प्रौढ़ लेखकों को भी लिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

डॉ. हरविंदर सिंह ने कहा कि चौहान की कहानियों और उपन्यासों की भाषा अत्यंत भावपूर्ण होती है, यही कारण है कि उनके पाठकों का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर प्रिंसिपल अमनदीप कौर, कोऑर्डिनेटर परमप्रीत कौर, वैद्य एवं समाजसेवी कपूर चंद शर्मा तथा पंजाबी कवि हाकम सिंह रूड़ेके भी उपस्थित रहे।

हमें सतर्कता से करना चाहिए डिजिटल प्लेटफार्म का प्रयोग : मनोज कुमार

चिड़ाव, 17 अप्रैल (प्रवीन कुमार) : जिले के गांव बांसा में आरोह फाउंडेशन के वित्तीय साक्षरता केंद्र चिड़ाव द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें डीडीएम हिमांशु खत्री और आरोह फाउंडेशन के जिला समन्वयक मनोज कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कैंप में वित्तीय साक्षरता केंद्र चिड़ाव की वित्तीय सलाहकार रेनू बाला, सहायक वित्तीय सलाहकार सुमन और अनु देवी भी मौजूद रहीं। ग्रामवासियों ने इस कैंप में बढ़-चढ़कर भाग लिया और बैंक खातों से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं और लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिला समन्वयक मनोज कुमार ने ग्रामीणों को बचत की विभिन्न योजनाओं जैसे कि आरडी, एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। मनोज कुमार ने उन्हें अटल पेंशन योजना के विषय में बताते हुए कहा कि अटल पेंशन योजना एक निवेशकों योजना है जिसमें हमारे साथ साथ हमारे जीवनसाथी को भी पेंशन का प्रावधान है और बच्चों के लिए भी अच्छी राशि मिलती है। वित्तीय सलाहकार रेनू बाला ने ग्रामीणों को डिजिटल प्लेटफॉर्म व फ्रॉड के विषय में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हमें सतर्कता से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करना चाहिए इसके अतिरिक्त उन्होंने बैंक खाते में नॉमिनी के महत्व के बारे में बताया। सहायक वित्तीय सलाहकार सुमन ने सभी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के विषय में बताया कि केवल 456 रुपए देकर हम 4 लाख की आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सहायक वित्तीय सलाहकार अनु देवी ने सभी को पब्लिक प्रोविडेंट फंड के विषय में बताया कि बचत करने का यह भी एक अच्छा विकल्प है। डीडीएम हिमांशु खत्री ने ग्रामवासियों को वित्तीय साक्षरता केंद्र चिड़ाव और नाबार्ड की अन्य योजनाओं के विषय में बताया और उन्हें केसीसी और पीकेसीसी के बारे में भी बताया। कैंप में उपस्थित ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं भी साझा कीं और उनका समाधान किया गया। इस कैंप का उद्देश्य ग्रामवासियों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करना और उन्हें विभिन्न वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना था।

फसल कटाई के बाद फानों में आग न लगाकर प्रबंधन करें : डॉ. आनंद कुमार शर्मा

करनाल, 17 अप्रैल (प्रवीन) : उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि गेहूं की फसल की कटाई का कार्य जारी है। फसल कटाई के बाद किसान अक्सर फसल अवशेषों को आग लगा देते हैं ऐसा करने से न केवल हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है बल्कि हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि खेतों में गेहूं की फसल कटाई के बाद फानों में आग न लगाएं, बल्कि उनका समुचित प्रबंधन करें। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से हमारा पर्यावरण दूषित होता है जिसकी वजह से हमें भंयकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फसल अवशेष जलाने से हमारी पैदावार पर असर पड़ता है और उत्पादन लागत अधिक और आमदनी कम हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, लाभदायक कीट/जीवाणुओं का समाप्त होना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगजनी करने वाले किसानों पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है जिसमे 2 एकड़ तक 5 हजार रुपये, 5 एकड़ तक 10 हजार रुपये तथा 5 एकड़ से ज्यादा 30 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आगजनी के दोषी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी व उसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे आगजनी के दोषी किसान अगले दो सीजन अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे।

विद्यालय शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, विद्यार्थियों का होता है सर्वांगीण विकास : योगेंद्र राणा

जे.पी.एस अकादमी का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम रहा शत-प्रतिशत

चिड़ाव, 17 अप्रैल (प्रवीन) : जे. पी. एस. अकादमी का 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। अकादमी में असंध विधायक व अकादमी संचालक योगेंद्र राणा ने पहुंच मेरिट में आने वाले बच्चों को मिठाई खिला कहा कि अकादमी का शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के निरंतर सहयोग का सशक्त प्रमाण है। विद्यालय की मेधावी छात्रा हरनूर कौर ने 96.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। छात्रा नव्या, दिव्या व रोमिल ने 96 प्रतिशत अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त, तनवीर कौर ने 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल कर विद्यालय नाम रोशन किया है। अकादमी के 5 छात्रों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक, 15 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक, 58 छात्रों ने 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो वहीं 77 छात्रों ने 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है। विधायक योगेन्द्र राणा व अंजू राणा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, नेतृत्व क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण पर विशेष बल देता है। प्रधानाचार्य बलराज सिंह ने कहा कि यह परिणाम हमारे विद्यार्थियों की लगन, शिक्षकों के समर्पण एवं अभिभावकों के विश्वास का सामूहिक प्रतिफल है। हम निरंतर गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर विधायक ने 10 वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में सभी मेरिट में आए बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

वांशिका रोहिल्ला ने 10वीं में 87 प्रतिशत अंक लेकर रचा सफलता का परचम, स्कूल में द्वितीय स्थान हासिल कर बढ़ाया मान

वांशिका शुरू से ही पढ़ाई में रही है मेधावी, हर कार्य को करती है पूरी लगन से पूरा : प्रिंसिपल नीता कुमारी

दिल्ली, 17 अप्रैल (ब्यूरो) : बी.एम. भारती मॉडल स्कूल, रामा विहार की होनहार छात्रा वांशिका रोहिल्ला ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 87 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में द्वितीय स्थान हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि से जहां स्कूल का नाम रोशन हुआ है, वहीं परिवार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। वांशिका ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही स्कूल परिसर में जश्न का माहौल बन गया। शिक्षकों और सहपाठियों ने वांशिका को बधाई देते हुए उसकी सफलता की सराहना की। विद्यालय की प्रिंसिपल नीता कुमारी एवं समस्त स्टाफ ने वांशिका की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उसने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि अपने व्यवहार और संस्कारों से भी विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने बताया कि वांशिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और हर कार्य को पूरी लगन से पूरा करती है। परिवार के सदस्यों ने भी वांशिका की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उसकी मेहनत और समर्पण आज रंग लाया है। उन्होंने कहा कि वांशिका ने पूरे परिवार का नाम गर्व से ऊंचा किया है। इस अवसर पर रिश्तेदारों, मित्रों और आसपास के लोगों ने भी वांशिका को बधाइयां देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वांशिका रोहिल्ला की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। उसकी यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

राष्ट्रीय मंच पर चमकी नरवाना की बेटी, मुकेश पंचाल का एस.डी. महिला महाविद्यालय में भव्य स्वागत

नरवाना, 17 अप्रैल (नरेन्द्र कुमार) : एस.डी. महिला महाविद्यालय नरवाना की एनएसएस छात्रा मुकेश पंचाल ने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी से महाविद्यालय का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिसर में प्राचार्या डॉ. अंजना लोहान व स्टाफ सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मुकेश पंचाल ने 12 और 13 अप्रैल 2026 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में देशभर से आए युवाओं के साथ संवाद कर उन्होंने अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। अपने अनुभव साझा करते हुए मुकेश पंचाल ने बताया कि इस मंच के माध्यम से उन्हें बजट, विकास योजनाओं और युवाओं की भूमिका को गहराई से समझने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें अपने विचारों को बेहतर तरीके से रखने की प्रेरणा दी। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अंजना लोहान ने छात्रा को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं और उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागरूक बनाती हैं। कार्यक्रम अधिकारी मधु शर्मा और मूर्ति जागलान ने भी मुकेश पंचाल की सराहना करते हुए कहा कि एनएसएस के माध्यम से छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मविश्वास का विकास होता है। इस अवसर पर डॉ. नयनदीप और सुश्री रेखा कोहली सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने भी छात्रा को बधाई दी और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अंत में सभी ने मुकेश पंचाल की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया।

डी.ए.वी. स्कूल का दसवीं कक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत

नीलोखेड़ी, 17 अप्रैल (सुरेश कुमार मिड्ढा) : डी.ए.वी. स्कूल ने दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शानदार उपलब्धि प्राप्त की। स्कूल का परिणाम शत-प्रतिशत परिणाम रहा। इस उत्कृष्ट सफलता से विद्यालय में खुशी और गर्व का माहौल है। स्कूल के प्राचार्य दीपक मिगलानी ने बताया कि 71 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 43 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए। अनय विद्यार्थियों ने 70 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रमुख विद्यार्थियों में सीरत (97.8 प्रतिशत), श्रुति (96 प्रतिशत), विशु (95.6 प्रतिशत), सिमरन (95.2 प्रतिशत), युविका (94.4 प्रतिशत), तनिशा (94 प्रतिशत), रिद्धिमा शर्मा (94 प्रतिशत), ओव्या (93.8 प्रतिशत), साक्षी (93.4 प्रतिशत), जश्न (93 प्रतिशत), सिमरनजीत (92.8 प्रतिशत), प्रेरणा (92.6 प्रतिशत), हिमांशी (92.6 प्रतिशत), अरविंद (92.2 प्रतिशत), लविश (92.2 प्रतिशत), शगुन (92 प्रतिशत), आयुष (91.4 प्रतिशत), मानवी (90.6 प्रतिशत), अर्शिया (90.4 प्रतिशत) तथा रिद्धिमा सिसोदिया ने (90 प्रतिशत) हासिल किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक मिगलानी ने विधार्थियों की गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए इसका श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल रहा। यह परिणाम विद्यालय की उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

नागरिक सुविधाओं की नियमित निगरानी करें वार्ड समितियां : सुमन बहमनी

वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने वार्ड समितियों से किया संवाद, दिया स्वच्छ-समृद्ध वार्ड का मंत्र

शहर के डीएवी कॉलेज में वीसी के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका रादौर व साढ़ौरा की वार्ड समितियों से सीएम ने किया सीधा संवाद

यमुनानगर, 17 अप्रैल (दिनेश कुमार) : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी नगर निकायों की वार्ड समितियों के साथ बैठक कर जनभागीदारी आधारित शहरी प्रशासन को और मजबूत करने का संदेश दिया। शहर के डीएवी कॉलेज में आयोजित इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका रादौर और साढ़ौरा की वार्ड समितियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने वार्ड स्तर पर जन सुविधाओं की निगरानी, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। बैठक में मेयर सुमन बहमनी, नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद, अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी अभिश्रुति, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, रादौर नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता, साढ़ौरा नगरपालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा, सचिव सुरेंद्र मलिक सहित वार्ड समितियों के अध्यक्ष व सदस्य मौजूद रहे। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि शहर का हर वार्ड जीरो वेस्ट वार्ड बने, इसके लिए वार्ड समितियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने पार्षदों, समिति अध्यक्षों और सदस्यों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, गलियों-नालियों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि हमारा वार्ड सबसे सुंदर, साफ और स्वच्छ बने, यह केवल निगम की नहीं बल्कि हर वार्डवासी की जिम्मेदारी है। जनभागीदारी से ही शहर को स्वच्छता में नई पहचान मिल सकती है। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने कहा कि वार्ड समितियां नगर निगम और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने समिति सदस्यों से अपील की कि वे सफाई व्यवस्था, कचरा उठान, सार्वजनिक शौचालयों और अन्य नागरिक सुविधाओं की नियमित निगरानी करें, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता बढ़ाकर ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाया जा सकता है, और वार्ड समितियां इस मिशन की सबसे अहम इकाई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वार्ड समितियों से संवाद किया। उन्होंने हरियाणा नगरपालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम-2008 के तहत गठित वार्ड समितियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि ये समितियां नगर निकाय और आमजन के बीच सबसे प्रभावी संवाद सेतु हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि वार्ड समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, नालियों, सार्वजनिक सुविधाओं और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी रखें तथा शिकायतों को तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाएं। वार्ड समितियों से मिलने वाली शिकायतों और सूचनाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वार्डों को सबसे स्वच्छ और सुंदर बनाने, अधिक पौधारोपण करने, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य कर समय पर जमा कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने का आह्वान किया।

केजरीवाल और जज के बीच बहस का वीडियो हटाने का आदेश

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और जज के बीच बहस के वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो में केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस शर्मा को हटाने की अपनी अर्जी पर बहस करते दिख रहे हैं। वहीं, हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जज से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अब इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया से इन वीडियो को हटवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह एक्साइज पॉलिसी केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने बहस कर रहे अरविंद केजरीवाल की बिना इजाज़त वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हटा दे। क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही की बिना इजाजत रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। ऑनलाइन सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट के नियम कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड करने और पब्लिश करने पर रोक लगाते हैं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल 13 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के सामने खुद पेश हुए थे और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की अपनी अर्जी पर बहस की थी। केजरीवाल ने तकरीबन एक घंटे से ज्यादा बहस की थी। सुनवाई के तुरंत बाद, कोर्ट के सामने उनकी बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अरविंद केजरीवाल के बाद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया। बता दें कि जांच एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को शराब नीति में हेरफेर के कारण शराब निर्माताओं से रिश्वत मिली।

दिल्ली की सड़कों पर राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी प्रतीकों से सजे ऑटो रिक्शा

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) अमेरिकी दूतावास ने स्वाधीनता 250 अभियान की शुरुआत की है, जिसमें दिल्ली की खास पहचान आटो रिक्शा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रतीकों से सजे हुए नजर आ रहे हैं। ये हरे-पीले आटो हैप्पी बर्थडे अमेरिका और 250 वष पुराना लिखे हुए बैनरों के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। एक आटो के पिछले हिस्से पर ट्रंप का बड़ा फोटो, अमेरिकी झंडा और स्टैच्यू आफ लिबर्टी के साथ ये संदेश दिख रहा है। अमेरिकी राजदूत सेरगियो गोर ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि ये आटो पूरे दिल्ली में घूमेंगे और बाद में भारत के अन्य शहरों में भी जाएंगे। चार जुलाई को अमेरिका अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसमें यह आटो अमेरिका-भारत दोस्ती को और मजबूत करने का प्रतीक बताया जा रहा है। वहीं, दिल्ली की सड़कों पर ट्रंप वाले आटो देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं। यह आटो अमेरिका-भारत दोस्ती को और मजबूत करने के प्रतीक बताये जा रहे हैं।

सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट: 1.47 लाख छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) सीबीएसई 10वीं के परिणामों में इस वर्ष कंपार्टमेंट पाने वाले छात्रों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। 2026 में 1,47,172 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट मिली, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1,41,353 थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा घोषित 10 वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में जहां एक ओर अधिकांश विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। वहीं, दूसरी ओर कंपार्टमेंट लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इस वर्ष मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीबीएसई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 10 वीं कक्षा में कुल 5.95 प्रतिशत विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष 1,47,172 छात्रों को कंपार्टमेंट मिली है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आंकड़ों में हल्का उछाल देखने को मिला है। पिछले वर्ष 2025 में कुल 1,41,353 छात्रों (5.96 प्रतिशत) की कंपार्टमेंट आई थी। हालांकि, प्रतिशत के लिहाज से देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें मामूली अंतर दर्ज है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में सामान्य विद्यार्थियों के साथ- साथ दिव्यांग विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में दिव्यांग श्रेणी के कुल 9,523 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 9,443 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। जिनमें से 355 छात्र फेल अनुत्तीर्ण रहे है। इसको लेकर बोर्ड के विशेषज्ञों का कहना है कि जो विद्यार्थी इस बार किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सके हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी शैक्षणिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई द्वारा मई माह में दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी जिसमें। इसमें कंपार्टमेंट के अलावा अपनी तैयारी में सुधार करने वाले विद्यार्थी भी दोबारा परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। 10वीं कक्षा - कंपार्टमेंट और दिव्यांग छात्र आंकड़े

स्लीवलेस सूट पहनी डीयू की छात्रा को स्टेज पर नहीं मिली एंट्री

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) वीडियो में छात्रा ने दावा किया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को स्टेज पर सम्मानित करने के लिए चुना गया था। मगर आखिरी वक्त में उन्हें कथित तौर पर पहनावे के कारण एक अधिकारी ने स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। सारा ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने दावा किया है कि एक यूथ इवेंट में उन्हें सिर्फ स्टेज पर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने जो सूट पहना था वह स्लीवलेस था। छात्रा का नाम सारा शर्मा है और वह नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं। सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इवेंट के दौरान उनके साथ क्या-क्या हुआ इसकी जानकारी दी है। सारा ने बताया है कि इवेंट का शीर्षक नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज था। इवेंट 12 अप्रैल को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था। वीडियो में छात्रा ने दावा किया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को स्टेज पर सम्मानित करने के लिए चुना गया था। मगर आखिरी वक्त में उन्हें कथित तौर पर पहनावे के कारण एक अधिकारी ने स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। सारा ने बताया कि इस दौरान उन्हें काफी अजीब लगा। वे वीडियो में कहती हैं यह पूरी तरह से महिलाओं का एक सम्मेलन था, जिसका मतलब है कि यहां सभी पोर्टफोलियो महिलाओं को दिए गए थे। यहां मुख्य अतिथि के रूप में खुद मनसुख मांडविया जी आए थे, और मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था। जब मैं वहां पहुंची, तो मंत्रालय के अधिकारियों ने मुझे देखा और कहा कि आपने स्लीवलेस पहना है, इसलिए आप उनका सम्मान करने के लिए स्टेज पर नहीं कर जा सकती हैं। इसके बाद मेरी जगह किसी और को स्टेज पर भेज दिया गया। सारा के मुताबिक, इवेंट के लिए ड्रेस कोड के बारे में पहले ही बता दिया गया था। छात्राओं को ट्रेडिशनल ड्रेस पहने के लिए कहा गया था। कोई साड़ी पहनकर आया था तो कोई सूट सलवार। लेकिन यह कभी नहीं कहा गया था कि स्लीवलेस सूट पहनकर नहीं आ सकते।

मुकरबा चौक अंडरपास 98 प्रतिशत तैयार जाम से कब मिलेगी राहत

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली में बन रहा एक अंडरपास है। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग की कमान संभालने वाले कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को इस अंडरपास परियोजना का निरीक्षण किया। राजधानी दिल्ली में दिन प्रति दिन बढ़ रही आबादी से ट्रैफिक जाम होने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए अंडरपास, ओवरब्रिज, सुरंग वाली सड़कों जैसे तमाम ढांचे खड़े किए जा रहे हैं। इनमें से एक है, मुकरबा चौक। यह उत्तरी दिल्ली में बन रहा एक अंडरपास है। दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग की कमान संभालने वाले कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को इस अंडरपास परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अंडरपास का निर्माण कार्य 98 फीसदी पूरा हो चुका है। जल्द उद्घाटन कर इसे जनता के लिए खोले जाने की संभावना है। अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो यह अंडरपास बदली-रोहिणी और आजादपुर-जहांगीरपुरी के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे वाहनों को मुकरबा चौक के व्यस्त इंटरचेंज से होकर गुजरने की जरूरत नहीं होगी। रोजाना आने-जाने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा ठीक से होगा कि मुकरबा चौक पर कितना बुरा ट्रैफिक जाम लगता है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए अंडरपास जैक पुशिंग तकनीक और प्री-कास्ट आरसीसी बॉक्स संरचना के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। इसके बनने से आउटर रिंग रोड स्थित व्यस्त मुकरबा चौक पर ट्रैफिक दबाव कम होगा।

दिल्ली की एक ऐसी पुलिस चौकी जो 5 महीने से खुद बीमार

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दक्षिणी दिल्ली की जंगपुरा पुलिस चौकी में पिछले पांच महीनों से सीवेज लाइन ध्वस्त होने के कारण जलभराव की गंभीर समस्या है। दूषित पानी जमा होने से पुलिसकर्मियों के परिवार मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चुस्त पुलिसिंग की बात हो या क्राइम पर कंट्रोल, जनता पुलिस से हर पैमाने पर खरा उतरने उम्मीद रहती है। पर दक्षिणी दिल्ली में एक पुलिस चौकी ऐसी भी है, जो पांच महीने से खुद बीमार है। बात 1983 में स्थापित जंगपुरा पुलिस चौकी की हो रही है, जो निजामुद्दीन थाने के अधीन है। सरकारी क्वार्टर में रहने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार में आए दिन कोई न कोई मलेरिया और टायफायड जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। बुधवार को भी एक परिवार की एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट हुई। इन सबका कारण है, ध्वस्त सीवेज लाइन, जिसके कारण पिछले पांच महीनों से परिसर में दूषित पानी जमा है। हैरानी की बात तो ये हैं कि पुलिस चौकी से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही जल बोर्ड का स्थानीय कार्यालय है। लगातार शिकायतों के बाद भी बात निरीक्षण से आगे नहीं बढ़ पाई। चौकी परिसर में ही 13 सरकारी क्वार्टर बने हैं। वर्तमान में लगभग आठ में पुलिसकर्मी परिवार के साथ रहते हैं। क्वार्टर की ओर जाने वाले गेट के मुहाने पर ही सीवर का पानी भरा है। गंदे पानी में पैर रखना न पड़े इसके लिए थोड़ी-थोड़ी दूर पर पत्थर रखे हैं। अंदर जाने पर आंगन का हाल और भी बुरा। पानी सड़ने के बाद काला पड़ गया है। कीड़े पैदा हो गए हैं। मच्छरों के लार्वा जहां-तहां फैले हैं। परिसर में कहीं भी दो मिनट बैठना मुहाल है। मच्छर घेर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक, अब तक 15 से 20 बार मौखिक और चार बार लिखित शिकायत की गई। अंतिम लिखित शिकायत छह अप्रैल को की गई।

संशोधन विधेयक गिरा

पृष्ठ एक का शेष ...का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है जो एक ''शर्मनाक कृत्य'' है। उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि सरकार द्वारा जाति जनगणना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, ''पूरा विपक्ष मिलकर सरकार के इस प्रयास को विफल करने जा रहा है।'' उनका कहना था, ''कुछ सच्चाई यह सदन में बताने की जरूरत है। यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तीकरण से कुछ लेनादेना नहीं है। 2023 में जो पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था।'' लोकसभा में शुक्रवार को उस समय हल्के-फुल्के क्षण देखने को मिले जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने मजाकिया लहजे में कहा कि ''कानून मंत्री ने कल सदन में पत्नी को समर्पित कविता पढ़ी, जिसके बाद मुझे घर में बहुत डांट पड़ी।'' वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पीसी सरकार का 'मैजिक शो' या ''माइकल जैक्सन के डांस'' जैसा था। जब जातिगत जनगणना पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ उनकी नोकझोंक हुई। **राज्यसभा की कार्यवाही** - राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को मनोनीत सदस्य हरिवंश के उपसभापति पद पर निर्वाचित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री तथा सदन के नेता जे पी नड्डा ने हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया

पंजाब में केबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ....

पृष्ठ एक का शेष ... एक्स पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने लिखा, रहमान डकैत के सभी साथियों के नंबर भी आएंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सियासी टकराव और बढ़ सकता है। इस ब्यान को श्बष्ठ की रेड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार सुबह ईडी की टीमों ने लुधियाना में संजीव अरोड़ा के आवास समेत उनसे जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं के संबंध में की जा रही है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

तेवर दिखाने लगी गर्मी, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बुधवार

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 41 डिग्री और शनिवार को 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। रिज क्षेत्र 40.7 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। लगातार बढ़ती गर्माहट के बीच बुधवार (15 अप्रैल) का दिन गर्मियों के इस सीजन में अभी तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। दिन भर खिली रहने वाली तेज धूप के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री पार कर गया। शुक्रवार को इसके 41 व शनिवार को 42 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है। उधर, 11 दिन तक मध्यम श्रेणी में रहने के बाद बुधवार को राजधानी की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच गई। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह गर्मियों के इस सीजन के साथ-साथ इस वर्ष का भी अभी तक सबसे ज्यादा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। 40.7 डिग्री सेल्सियस के साथ रिज क्षेत्र बुधवार दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा। न्यूनतम तापमान मुंगेशपुर में सर्वाधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 73 से 17 प्रतिशत रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज धूप भी निकली रहेगी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमश: 40 और 21 डिग्री के आसपास रह सकता है।

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों को झटका

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस भंभानी ने कहा कि उन्हें कोई गलती नहीं दिखती। कोर्ट ने आरोपियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 21 मई को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को पिछले साल अगस्त में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा की तरफ से पेश हुए वकील की ट्रायल पर रोक की अर्जी को खारिज कर दी। वकील ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है, जब सबूत पेश होने शुरू होने हैं। ट्रायल कोर्ट पहले ही मेडिकल चीफ, मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) तैयार करने वाले एग्जामिनर और मुख्यमंत्री के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) को तलब कर चुका है। जस्टिस भंभानी ने आरोपियों की ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मैं किसी चीज पर तब तक रोक लगाने में विश्वास नहीं करता जब तक मुझे यह साफ न हो कि कुछ गलत हो रहा है या होगा। मुझे यहां ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब दोनों लोग दिल्ली के रहने वाले नहीं थे तो गुप्ता की जन सुनवाई में क्यों थे? जस्टिस भंभानी ने कहा कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आप दिल्ली में क्यों थे?

10 करोड़ की लागत से नैनी झील बनेगी पर्यटन हब

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) मॉडल टाउन स्थित नैनी झील के सुधार और सौंदर्यीकरण की योजना एक बार फिर सामने आई है। यह परियोजना पिछले पांच से दस सालों से राजनीतिक विवादों, प्रशासनिक बाधाओं और टेंडर समस्याओं के कारण लंबित थी। मॉडल टाउन स्थित नैनी झील के सुधार एक बार फिर प्लान सामने आया है। एमसीडी ने झील के सुधार और सुंदरीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। पांच साल से यह परियोजना काफी राजनीतिक दलों के झगड़े तो कभी प्रशासनिक उलटफेर की वजह से लंबित पड़ी है। जबकि नैनी झील एक बेहतर पर्यटन स्थल के तौर पर माना जाता है। रिहायशी क्षेत्र के बीच बनी इस झील में दूर-दराज से पर्यटक आते हैं। इस झील की गंदगी को साफ करने के साथ ही झील के चारों तरफ सुंदरीकरण होना है। साथ ही झील में पर्याप्त पानी रहे इसके लिए जलमल शोधित सयंत्र (एसटीपी) का पानी भी पाइपलाइन के जरिये लाना था। झील के सुधार सबसे पहले परियोजना 2015-16 में आई। जब तत्कालीन आप सरकार में पर्यटन मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने झील को टूरिज्म हब बनाने और इसके पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए एक विस्तृत योजना की घोषणा की थी। इसमें शिकारा बोट्स और लेजर शो जैसे आकर्षण शामिल थे। लेकिन वह भी अभी तक फाइलों से जमीन पर नहीं निकला है। इतना ही नहीं 2022 में केंद्र सरकार ने जब एमसीडी की फंड की कमी को देखते हुए जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ की वित्तीय मदद की तो भी एमसीडी इस योजना को फाइलों से जमीन पर नहीं उतार सकी। 2022 में निगमों के एकीकरण के बाद स्थायी समिति का गठन न होने से इस परियोजना को मंजूरी न मिलने की वजह से 2025 तक यह मामला लटका रहा। इतना ही नहीं एमसीडी ने निविदा आमंत्रित की तो एक ही बोली आने की वजह से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब 2026 में एमसीडी ने फिर इसके सुधार के लिए निविदा आमंत्रित की है। जिसमें 10 करोड़ की लागत से झील का सुधार और सुंदरीकरण का कार्य होगा।

दिल्ली की सड़कों पर गायब निशान राहगीर और चालक दोनों परेशान

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) दिल्ली की सड़कों पर, खासकर द्वारका और उत्तम नगर में, ज़ेबरा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर की लकीरें गायब हैं। इससे चालकों और पैदल यात्रियों दोनों को यातायात नियमों को समझने में दिक्कत होती है। सुरक्षित यातायात के लिए सड़कों पर बनी लकीरों का अपना एक विशेष महत्व है। चालक दूर से ही इन लकीरों का अर्थ समझकर अपनी चाल दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन जब लकीरें नजर ही न आएं तो फिर क्या होगा। उपनगरी द्वारका हो या उत्तम नगर या फिर कोई और इलाका, कई जगह आपको ये लकीरें ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगी। अधिकांश जगहों पर जेब्रा क्रासिंग की लकीरें नजर नहीं आती। बड़ी सड़कों पर तो कहीं कहीं धूमिल लकीरें नजर आ भी जाएं लेकिन कम चौड़ी सड़कों पर तो इनका दिखना दुर्लभ हैं। क्षेत्र की बात करें तो नजफगढ़ मेन रोड, नजफगढ़ नांगलोई रोड, ढांसा मेन रोड, कापसहेड़ा मेन रोड, डाबड़ी-पालम रोड, पंखा रोड, लाल साईं मार्ग सहित अधिकांश सड़कों के दो तिहाई हिस्से पर बनी लाल बत्ती पर आपको जेब्रा क्रासिंग की लकीरें नजर नहीं आती हैं। द्वारका उपनगरी में भी अधिकांश जगहों पर इन लकीरों को नजर आना दुर्लभ है। उपनगरी का सर्वाधिक व्यस्त आशीर्वाद चौक चौराहा और इसके आसपास नजर डाल लें तो आपको अधिकांश जगह किसी भी प्रकार की लकीर दिखाई नहीं देगी। यह स्थिति यहां इसलिए गंभीर है क्योंकि रात के अंधेरे में यहां सड़कों पर रोशनी का इंतजाम न के बराबर है, ऐसे में यहां स्थिति गंभीर हो जाती है। द्वारका से थोड़ी ही दूर डाबड़ी-पालम रोड या पंखा रोड के कुछ हिस्से में जेब्रा क्रासिंग की लकीरें बड़ी मुश्किल से नजर आती हैं। दूर से तो यह आपको नजर नहीं आएंगे, हां पास आने पर हल्की हल्की दिखाई देती है। यातायात पुलिस के मुताबिक सड़क सुरक्षा से नियम के तहत प्रत्येक लाल बत्ती पर जेब्रा क्रासिंग का होना अनिवार्य है। जेब्रा क्रासिंग का प्रविधान पैदल यात्रियों के लिए किया जाता है ताकि वे लाल बत्ती पर वाहनों के रुकने के बाद सड़क पार कर सकें। जहां लाल बत्ती नहीं है और केवल जेब्रा क्रासिंग है।

सार्वजनिक जगहों पर गाड़ियों में शराब पार्टी, दिल्ली में कानून-व्यवस्था पर सवाल

नई दिल्ली 17 अप्रैल (निस) वसंत एन्क्लेव में सड़क पर कार में बैठकर शराब पीने से मना करने पर सेना के एक अधिकारी व उनके बेटे से 11 अप्रैल की रात मारपीट की गई। इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक इलाके का मामला नहीं है। पूरी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गाड़ी में बैठकर शराब पीने का चलन बढ़ रहा है। खासकर होटल, ढाबों और फास्ट फूड स्टाल के बाहर शाम होते ही इस तरह के नजारे आम हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर खुलेआम शराब पीते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस तरह के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां ऐसे करीब 54 हजार से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 60 हजार से अधिक हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह प्रवृत्ति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आसपास के माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अमृतपाल सिंह प्रिंटर, पब्लिशर व संपादक ने जेएसडी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईजी प्रिंटर्स प्रा.लिमि., 104, डीएसआईडीसी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-20 के मालिक/कीपर जगपाल सिंह से छपवा कर कार्यालय दैनिक भारत देश हमारा 24/34 तिलक नगर नई दिल्ली से प्रकाशित किया।
PRGI (RNI) Regd. No.57282/1994